भाजपा का आरोप पत्र

कांग्रेस नेतृत्व

की संप्रग सरकार के कुशासन पर

Hkkjrh; turk ikVhZ }kjk izdkf'kr] 11] v'kksd jksM] ubZ fnYyh & 110 001

कांग्रेस नेतृत्व की संप्रग सरकार के दस वर्षों का कालायुग
भाजपा का आरोप–पत्र
प्रस्तावना

2004 में राजग सरकार के सत्ता से हटने के समय तक हमने भारत को खुशहाली के उस दौर में ला खड़ा कर दिया था जो कि भौगोलिक और लोकतान्त्रिक सुदृढ़ता के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा था। 2004–05 के आर्थिक सर्वे में इस तथ्य का उल्लेख श्री पी. चिदम्बरम् द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था "कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों एवं उद्योग एवं सेवाओं के क्षेत्र में हुए बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था ने वर्ष 1975–76 और 1988–89 के वर्षों को छोड़कर 2003–04 के वित्त वर्ष में में अब की बेहतरीन वृद्धि दर दर्ज की है"। यह महत्वपूर्ण है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह आर्थिक प्रगति पोखरण परमाणु परिक्षण के बाद भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबन्ध, पूर्वी एशिया में व्याप्त संकट, गुजरात में विनाशकारी भूकम्प, ओडिशा में चक्रवाती तूफान और 2001 और 2002 के सूखे के संकटों के बावजूद दर्ज की गई था।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार तब से लेकर आज तक सत्ता में है। अगर आज पीछे मुड़कर देखा जाए तो बीता दशक प्रगति के तमाम अवसरों को गंवाने के कालेयुग के रूप में याद किया जाएगा। यह दशक दिशाहीन और उदासीन नेतृत्व का भी रहा है। भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े कारनामों के बीच शासन करने की प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति का सर्वथा अभाव दिखा।

सरकार की अकर्मण्यता से देश की सीमा और संप्रभुता का लगातार उल्लंघन होता रहा, जिसके कारण प्रत्येक भारतीय के सम्मान को ठेस पहुंची। पड़ोसी देश द्वारा सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट लिए गए लेकिन सरकार ने कोई ठोस प्रतिरोध तक दर्ज नहीं करवाया बल्कि इन जवानों के सर कटे पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए।

मंत्रालय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया असमंजसता और जटिलता की भेंट चढ़ गई। भारत सरकार में वर्ष 1993–2001 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे प्रो. शंकर आचार्य का कहना है कि "मुख्यतः UPA सरकार के शासन का दशक भारत के दूरगामी विकास के लक्ष्यों के दृष्टिगत आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहा बावजूद इसके कि इन वर्षों में निवेश और उच्च विकास के तमाम अवसर उपलब्ध रहे। निष्कर्ष यह है कि इस सरकार की आर्थिक विरासत बदसूरत तो नहीं लेकिन बुरी अवश्य रही है" http://www-business-standard-com/article/opinion/shankar-acharya-upa-s-economic-legacy-good-bad-or-ugly-114022501240_1-html

विशेषकर UPA-II के दौरान केबिनेट ने वस्तुतः काम किया ही नहीं इसका स्थान GOMS, EGOMS और गैर–संवैधानिक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के हस्तक्षेप ने ले लिया। Business World ने 16 दिसम्बर 2013 को अपनी एक रिपोर्ट में "Panel Overload" की संज्ञा देते हुए लिखा है सामूहिक निर्णय और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कुल 30 Groups of Ministers और Empowered groups of Ministers का गठन किया गया। लेकिन इनके प्रभावी होने के विषय में जिनता कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। कुछ मंत्री तो 27 से लेकर 6 Groups of Ministers के सदस्य थे''।

UPA शासन के दौरान निवेश और GDP अनुपात 4% तक घट गया। कुछ सक्षम लोगों द्वारा देश की पूंजी को देश से बाहर ले जाया गया। जिन चीजों का उत्पादन और निर्यात हमारे देश से हो सकता था, उनको आयात किया गया। यह केवल कॉर्पोरेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि MSME सेक्टर में भी हुआ। बिना विकास के रोजगार पैदा नहीं हो सकते, आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। श्रम, जमीन, जंगल/पर्यावरण और उच्च ब्याज दर के कारण निवेश नहीं हो रहा है।

UPA 2 सरकार के गठन के तुरंत बाद सरकार ने बड़ी ही नेक घोषणा की थी कि अगले 100 दिन के अन्दर महंगाई को नियंत्रित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महंगाई पर लागम लगाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा के द्वारा प्रस्ताव भी पास किये गए, लेकिन जरूरी वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की आकाश छूती महंगाई को कम करने के लिए कुछ भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाये। अंतिम 5 वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति 10% तक जा पहुँची जिसकी वजह से परिवारों में पोषण की आपूर्ति पर विपरीत असर पड़ा। देश के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय

ने सरकार को FCI के गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीबों में मुफ्त वितरित करने के लिए आदेश देना पड़ा।

यही इतिहास फिर से दोहराया गया जब 2G Spectrum allocation केस में प्रधानमंत्री कार्यालय की दलीलों से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने PMO को हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया।

कोल आवंटन में हुई धांधली के प्रकरण की सुनवाई करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कानून अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कोयला आवंटन घोटाले में आरोपियों की जांच और मुकदमा चलाने के सरकार के मार्गदर्शन लेने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में काम करें। मंत्रियों और अधिकारियों ने कोर्ट के इस निर्देश की खुले आम अवहेलना की जिसकी वजह से मंत्रियों के शर्मनाक इस्तीफे तक हुए।

यह सरकार GDP में वृद्धि को लेकर अथक बातें करती रही, लेकिन घटते रोजगार और सड़कों पर उतर रहे निराश युवा शक्ति की ओर सरकार ने अपनी आँखें मूँद ली। मौजूदा सरकार ने लम्बे समय से जनता का विश्वास खो दिया था। इस सरकार ने जनता को बार–बार नीचा दिखाया और प्रदर्शन करने में बुरी तरह नाकाम रही।

Pew Research Group की एक रिपोर्ट (Feb 26, 2014) के अनुसार "जिस प्रकार से देश में चीजें घटित हो रही हैं उसके कारण प्रत्येक 10 में से 7 भारतीय नाखुश हैं" http://www-pewglobal-org/2014/02/26/indians-want-political-change/

इस पृष्ठभूमि के साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में UPA पर शासन में विनिर्दिष्ट चूक और कमीशन के आरोप लगाती है।

घोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करने में विफल रहने और मंत्रालयों द्वारा समय पर और कुशलता पूर्वक काम न कर पाने की असफलता की वजह से यह आरोप लगाये जाते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने NDA शासन द्वारा विरासत में छोड़े गए बेहतर अर्थव्यवस्था और अवसरों को व्यर्थ में गँवा दिया।

2014 के चुनावों की घोषणा के समय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, "मैंने कम बात की है। मेरे लिए मेरा काम बोलेगा"।

कांग्रेस नीत UPA गठबंधन सरकार विरासत में भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थानों को नीचा दिखाने की वसीयत को छोड़ कर जा रही है, जिसे कोई भी अपनाना नहीं चाहेगा। भारत में एक जीवंत और गौरवशाली लोकतंत्र है। इसकी पुरातन संस्कृति और सहज विचारधारा ने देश नीतिगत और न्यायगत संस्थाओं का निर्माण किया है, उन्हें मजबूत किया है।

वंशवाद की राजनीति को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने पार्टी ने हमारे देश के राजनीतिक ढांचे में निहित नियंत्रण और संतुलन के फासीवादी तरीकों से खत्म करने का काम किया है। नतीजतन देश की विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे CAG, लोक लेखा समिति (PAC), संयुक्त संसदीय समिति (JPC), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का कामकाज व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुआ है।

आरोपों को तैयार करने के लिए स्रोत निम्नलिखित हैं.

- कांग्रेस पार्टी का वर्ष 2009 का घोषणा पत्र।
- "प्रगति और विकास के 10 वर्ष 2004–2014"– वर्ष 2014 के आरम्भ में जारी।
- CAG की रिपोर्टें।
- मीडिया की रिपोर्टें।
- आम जनता से प्राप्त जानकारी, SMS के माध्यम से जनता की राय, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और ट्विटर के जरिये जुटाए गए तथ्य।
- गुवाहाटी में जुटे 8 राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत और उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन। इसी प्रकार का आयोजन मुंबई में भी हुआ।
- विशिष्ट क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञों की राय।

विषय सूची

प्रस्तावना

1.0 प्रधानमंत्री पद की गरिमा और समग्रता के साथ समझौता

2.0 भारत की अर्थव्यवस्था का विनाश

- 2.1 आर्थिक विकास के सभी आधारों को नष्ट करना
- 2.2 रूपये के मूल्य में गिरावट
- 2.3 महंगाई को नियंत्रित करने में भारी असफलता
- 2.4 रोजगार सृजन में असफलता
- 2.5 आधारभूत ढांचे के विकास में असफलता

3.0 घोटालों और भ्रष्टाचार की एक अंतहीन गाथा

4.0 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ

- 4.1 बाहरी खतरा
- 4.2 आंतरिक सुरक्षा

5.0 विदेश नीति की विफलता

6.0 पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा

7.0 शिक्षा एवं स्वास्थ्य

8.0 सस्थानों की महत्ता को कम करना

9.0 कांग्रेस घोषणा पत्र 2009 में उल्लेखित वादों में विफल रहने पर आरोप (कांग्रेस घोषणापत्र के क्रमानुसार सूचीबद्ध)

- 9.1 आतंकवाद
- 9.2 विशेष बटालियनों की स्थापना
- 9.3 UIDAI आधार पहचान पत्र
- 9.4 रक्षा तैयारी
- 9.5 उर्जा सुरक्षा
- 9.6 राजकोषीय मितव्ययिता और महंगाई
- 9.7 किसानों की भलाई
- 9.8 कृषि उत्पादों का संचलन
- 9.9 पंचायती राज
- 9.10 GST

10.0 निष्कर्ष

11.0 अध्याय 2 का एक संक्षिप्त सार

समझौता

प्रधानमंत्री पद की गरिमा

और विश्वसनीयता के साथ

1.0 प्रधानमंत्री पद की गरिमा और विश्वसनीयता के साथ समझौता

- भारत के प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रधानमंत्री केवल सरकार का ही मुखिया नहीं होता है बल्कि वह देश का भी नेता होता है। आखिरी फैसला लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए तथा उनका निर्णय अन्तिम होना चाहिए। एक प्रभावी सरकार चलाने के लिए तीन बातें अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम नेतृत्व दिशा प्रदान करने वाला नेतृत्व, जिसमें निर्णय लेने और उनको लागू करने की क्षमता हो। दूसरा है सरकार की विश्वसनीयता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है–सत्ता में सरकार का इकबाल।

- कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीतिक संरचना की स्थापना की थी, वह स्वाभाविक त्रुटिपूर्ण थी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले बोर्ड के CEO के रूप में कार्य किया, जहाँ राहुल गांधी श्रीमती सोनिया गाँधी के डिप्टी थे। स्वाभाविक रूप से वह एक स्वाभाविक नेता और नीति निर्धारित करने वाले नेता नहीं बन सके। पूर्व में भी इस प्रकार के नेता हुए हैं जो बेशक प्रधानमंत्री बनते समय राष्ट्रीय स्तर के न रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की और इस पद की गरिमा को बढ़ाया। जबकि मनमोहन सिंह इस मोर्चे पर बुरी तरह विफल रहे। मंत्रियों ने बतौर टीम काम नहीं किया। कई अवसरों पर मंत्रियों ने डॉ. मनमोहन सिंह की अनदेखी की जिसकी वजह से सरकार के संचालन पर बुरा असर पड़ा।

- इस वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई, जहाँ मंत्रियों ने निरंकुश होकर अपने अपने मंत्रालयों का संचालन किया। प्रधानमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं था। आपराधिक लापरवाही और शर्मनाक घोटालों पर आश्चर्यजनक उदासीनता प्रधानमंत्री के कार्यकलाप का पर्याय बन गया। इन घोटालों और जनता के पैसे की लूट को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने किसी भी अवसर पर सक्रियता नहीं दिखाई। घोटालों के कई प्रकरणों में स्वयं प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका गंभीर जांच का विषय है।

- भारत की राजनीति की यह विचित्र त्रासदी रही है कि डॉ. मनमोहन सिंह अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार थे। एक अवसर पर राहुल गांधी ने उनकी ही सरकार द्वारा मंजूर एक विधेयक को बकवास बताकर उसे फाड़कर फेंकने की सार्वजनिक घोषणा कर दी, फिर भी डॉ. मनमोहन सिंह अपमान के इस घूँट को पीकर कुर्सी पर जमे रहे। वह पूर्व विदेश सचिव से भी सीख नहीं ले सके। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा सार्वजनिक तौर पर अपमानित किये जाने के बाद तत्कालीन विदेश सचिव श्री वेंकटेश्वरन ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस सर्वोच्च पद की विश्वसनीयता, गरिमा और निष्ठा के साथ समझौता किया तथा इसका जबरदस्त अवमूल्यन करते हुए आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार की अगुआई की। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया, उससे उनके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के दावे पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। डॉ. मनमोहन सिंह की नेतृत्व में भारत की छवि पर गंभीर आघात हुए हैं।

- प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को नष्ट करने में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी बराबर के भागीदार हैं। वे बिना किसी उत्तरदायित्व और जवाबदारी के सत्ता की असीमित शक्तियां अपने पास रखना चाहते थे। कई अवसरों पर गलतियाँ और अनियमितताएं इन दोनों के स्वीकृति और अनुमोदन से हुई हैं। इन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की लूट पर रोक लगाने के लिए अपनी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया बल्कि प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग किया।

विनाश

भारत

की अर्थव्यवस्था का

2.0 भारत की अर्थव्यवस्था का विनाश :
10 वर्ष के कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन के कुशासन में अर्थव्यवस्था का भारी कुप्रबंधन

2.1 आर्थिक विकास के सभी आधारों को नष्ट करना

- वर्ष 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब राजग सरकार सत्ता में आई थी तब भारत की विकास दर मात्र 4.3% थी। एक प्रेरक नेतृत्व, बेहतर नीतियों की शुरुआत, बेहतर शासन और प्रबन्धन की बदौलत हमने इस विकास दर को उच्चतम स्तर तक पहुँचाया। मई 2004 में जब राजग सत्ता से बाहर हुआ तब देश के अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व 8.5% के स्तर पर थी। राजग सरकार ने अर्थव्यवस्था की बेहद मजबूत नींव रखी, जिसमें महंगाई नियंत्रित थी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई थी तथा विकास के एक समान अवसर उपलब्ध थे।
- राजग ने विपरीत परिस्तिथियों के मध्य श्रेष्ठ प्रदर्शन किया : राजग का प्रदर्शन इसलिए भी उल्लेखनीय है कि मुश्किल परिस्तिथियों और प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के दौरान हासिल किया गया था। पोखरण परमाणु परिक्षण के बाद भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबन्ध, कारगिल युद्ध, संसद पर आतंकवादी हमला, पूर्वी एशिया में व्याप्त संकट, गुजरात में विनाशकारी भूकम्प, ओडिशा में चक्रवाती तूफान और 2001 और 2002 के सूखे के संकटों के बावजूद यह विकास दर दर्ज की गई थी। UPA सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा 2004–05 में प्रकाशित आर्थिक सर्वे भी इन तथ्यों को स्वीकार करता है।

  "कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों एवं उद्योग एवं सेवाओं के क्षेत्र में हुए बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था ने वर्ष 1975–76 और 1988–89 के वर्षों को छोड़कर 2003–04 के वित्त वर्ष में अब तक की बेहतरीन वृद्धि दर दर्ज की है"।

  यह वास्तव में एक त्रासदी है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने विरासत में प्राप्त उच्च विकास दर के लाभ को पूरी तरह गंवा दिया और विकास की दर में 5% की भारी गिरावट के साथ इसे 4.8% पर पहुंचा दिया।
- **UPA सरकार को विरासत में समृद्ध अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई लेकिन उन्होंने उसे नष्ट कर दिया।** कांग्रेस नीत UPA सरकार राजग से प्राप्त बेहतरीन अर्थव्यवस्था को बरकरार नहीं रख सकी। वह विकास की उच्च दर को आगे ले जाने में नाकाम रही। एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कारकों को उसने सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया।

आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं

1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम राजकोषीय घाटा
2. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम चालू खाता घाटा
3. न्यूनतम महंगाई दर
4. उच्च बचत दर
5. विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में न्यूनतम विदेशी कर्ज
6. आधारभूत ढांचा

जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, राजग के अर्थव्यवस्था के प्रत्येक कारक में सत्ता में आने के बाद प्रगति दर्ज की और UPA के हाथों में एक बेहतर अर्थव्यवस्था सुपुर्द की और UPA ने उसका क्या हश्र किया? उसने अर्थव्यवस्था के हर घटक को व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया। जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे UPA द्वारा बदहाल की गई

अर्थव्यवस्था से जूझना पड़ेगा।

क्रमांक सूचक	1997–98	2003–04	2012–13	2013–14
1 सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर	4.3%	8.5%	4.96%	4.6% (till Dec. 2013)
2 औद्योगिक वृद्धि–दर	4.01%	7.32%	2.1%	–2% (मनुफैक्चिरिंग)
3 सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का %	5.66%	4.34%	5.2% (5.7% 2011–12 में)	
4 बचत दर – सकल घरेलू उत्पाद का %	24.1%	32.41% 2004–05 में	30.2%	
5 चालू खाता घाटा – सकल घरेलू उत्पाद का%	–2%	+2.7% (अधिशेष)	–4.8% (घाटा)	
6 विदेशी कर्ज (अरब डॉलर में)		$112.7 billion	$390 billion	
7 लघु अवधि का बाहरी कर्ज– सकल घरेलू उत्पाद का %		3.9%	24.8%	

2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% के राजकोषीय घाटे को योजना व्यय में 90000 करोड़ रुपये की कटौती के द्वारा प्राप्त किया जा सका। 2013–14 में भी 4.6% के राजकोषीय घाटे को योजना व्यय में 79790 करोड़ रुपये की कटौती करके पूरा किया गया।

योजना व्यय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि इसके माध्यम से नई एवं आधारभूत से जुडी परियोजनाओं में खर्च होता है. योजना व्यय में भारी पैमाने पर कटौती करके UPA सरकार ने भविष्य के विकास के साथ समझौता किया है।

(बिंदु क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के श्रौत)

योजना आयोग के उपाध्यक्ष के योजना आयोग की डाटा बुक–दिनांक 18.12.2013

आर्थिक सर्वे 2004–05।

वित्त मंत्री का 2013–14 का बजट भाषण।

CSO का 2013–14 की तीसरी तिमाही के लिए आंकलन।

(बिंदु क्रमांक 6 एवं 7 के श्रौत)

RBI की भारतीय अर्थव्यवस्था 2012–13 पर हैण्ड बुक।

अर्थव्यवस्था के घटकों को नष्ट करने के लिए UPA को देश से माफी मांगनी चाहिए

2.2 रुपये की कीमत में गिरावट

चालू खाता अधिशेष का घाटे में बदल जाना रूपये की कीमत में गिरावट का कारण बना है। रुपये की कीमत में

गिरावट से आयात महंगा हुआ है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल हैं, जो कि पूर्ण रूपेण विदेशों से आयात किये जाते हैं। इसकी वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी।

पिछले वर्षों में रूपये की कीमत डॉलर में

	1998–99	2003–04	29th August, 2013	March, 2014
एक डॉलर की कीमत (रूपये में)	42	45.9	67.7	61

(Source: RBI Handbook of Statistics)

2.3 महंगाई को नियंत्रित करने में भारी विफलता

महंगाई की सबसे अधिक मार गरीब पर पड़ती है, उसकी क्रय करने की शक्ति वर्ष दर वर्ष घट जाती है। राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे को नियंत्रित न कर पाने की वजह से रूपये की कीमत बढ़ी, जिसने आयात को महंगा बना दिया। UPA सरकार का महंगाई के ऊपर से नियंत्रण हट गया, जिसका खामियाजा गरीब और माध्यम वर्ग को झेलना पड़ा।

पिछले कुछ वर्षों में (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति की निम्न तालिका अपनी कहानी खुद बताती है।

वर्ष	**NDA**	**UPA**
1999–2000	3.4	
2000–2001	3.7	
2001–2002	4.3	
2002–2003	4.1	
2003–2004	3.8	
2004–2005		3.9
2005–2006		4.2
2007–2008		6.8
2008–2009		9.1
2009–2010		13.0
2010–2011		9.5
2011–2012		9.0
2012–2013		8.0
औसत	**3.86**	**7.93**

राजग के शासन काल में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.86 था जबकि यूपीए के शासन काल में यह औसत 7. 93 तक जा पहुंचा।

(Source : Planning Commission Data book for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013)

टिप्पणीः– **वर्ष 2009 में डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने सार्वजनिक तौर पर यह वादा किया था कि अगले 100 दिनों के अन्दर महगाई कम हो जायेगी, लेकिन उसके 5 साल भी जनता महंगाई से तडपती रही।**

2.4 रोजगार सृजन में असफलता

आधारभूत ढाँचे और उद्योगों की पूर्ण उपेक्षा से UPA सरकार का रोजगार सृजन करने के मामले में बुरी तरह विफल रही। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 1999–2000 एवं 2004–05 के दौरान 6 करोड़, 70 लाख रोजगार सृजित हुए, जबकि 2004–05 एवं 2011–12 के मध्य केवल 1 करोड़ 54 लाख रोजगार ही सृजित हो सके।

निम्न तालिका राजग और संप्रग शासनों के बीच प्रदर्शन में बुनियादी अंतर को दर्शाती है।

	1999–2000 से 2004–05	2004–05 से 2011–12
रोजगार की संख्या (मिलियन में)	60.7 (6.07 Cr)	15.44 (1.54 Cr)
औसत वार्षिक रोजगार सृजन (मिलियन में)	12.1 (1.21 Cr)	2.2 (22 लाख)

टिप्पणी: NDA के शासन में वार्षिक रोजगार सृजन 1.21 करोड़ से अधिक था जबकि UPA के दौरान यह घटकर महज 22 लाख प्रति वर्ष रहा गया। NDA के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने के वादा किया था और उसे पूर्ण किया। कांग्रेस ने 2009 में 100 दिन में महंगाई और बेरोजगारी कम करने का वादा किया था लेकिन वह ऐसा करने में बुरी तरह विफल रही।

यूपीए की विफलता और भी अधिक गहरी हो जाती है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक उत्पादक दो क्षेत्रों निर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन नहीं कर सकी। वास्तव में 2004–05 और 2009–10 के बीच विनिर्माण (मनुफैक्चिरिंग) क्षेत्र में 72.3 लाख नौकरियां खत्म हुईं, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि किस प्रकार से न्च। ने अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को नष्ट किया।

	रोजगार में कुल वृद्धि (लाखों में)	
	1999–2000 से 2004–05	2004–05 से 2009–10
मनुफैक्चिरिंग	117.2	–72.3
सेवा	187.7	–04.8

(Source: NSSO 61st, 66th and 68th Round Survey)

टिप्पणीः इसलिए राजग शासन के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार में वृद्धि के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार की व्यापक कुप्रबंधन के कारण रोजगार के अवसरों की हानि हुई और देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। विनिर्माण (मनुफैक्चिरिंग) और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का खत्म होना वास्तव में चौंकाने वाला है। राजग के दौरान खड़ी की गई विकास की इमारत यूपीए के काल में खंडहर बन गई।

2.5 आधारभूत ढांचे के विकास में असफलता

अच्छी आधारभूत ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। सड़कें, बिजली, लोहा एवं स्टील उद्योग, खनन

उद्योग जिसमें कोयला सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एवं बंदरगाह जहाँ से विदेशों के लिए व्यापार संचालित किया जाता है। यह सब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचे के मुख्य स्तम्भ हैं। वर्षों तक आधारभूत संरचना, लचर नीतियां, योजनाओं की मंजूरी में भ्रष्टाचार, घोटाले, विलम्ब से स्वीकृति, पर्यावरण मंत्रालय से मिलने वाली आवश्यक मंजूरी में देरी की वजह से हमारे बुनियादी ढांचे को अपंग बना दिया।

(a) सड़कें

भूतल परिवहन मंत्रालय से प्राप्त ये आंकड़े अपनी दुखद कहानी खुद बयाँ करते हैं।

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई (कि.मी.)	अतिरिक्त कि.मी	अवधि वर्ष	अतिरिक्त वार्षिक
1951	22193			
1997	34298	12105	46 वर्ष	**263**
2004	65569	31271	7 वर्ष	**4,467**
2012	76818	11249	8 वर्ष	**1,406**

46 वर्ष के शासन काल में कांग्रेस ने 12105 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जबकि 1997 से 2004 के अपने शासन काल के दौरान राजग ने 31271 किलोमीटर राजमार्गों क निर्माण किया. राजग सरकार ने प्रतिवर्ष 4467 Km की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया वहीं UPA के 2004 जव 2012 शासन में प्रतिवर्ष 1406 झउ राजमार्गों का निर्माण ही हो सका।

(Source : Basic Road Statistics from Ministry of Road Transport and Highways website http://www-morth-nic-in/showfile-asp\lid(839 and http://www-morth-nic-in/showfile-asp\lid)417)

(इ) बिजली

इस देश को कोयला घोटाले का खामियाजा कई प्रकार से भुगतना पड़ा. सरकारी खजाने को एक लाख करोड़ से अधिक के नुकसान के अतिरिक्त बिजली संयंत्रों को खराब कोयले एवं अनियमित आपूर्ति से उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। बिजली संयंत्रों के क्षमता के उपयोग का अनुमान प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) से पता चलता है। जो की तुलना से स्पष्ट रूप से राजग शासन संप्रग के साथ तुलना कैसे पता चलता है। यह मानक भी राजग सरकार को UPA से बेहतर साबित करता है।

बिजली संयत्रों का प्लांट लोड फैक्टर

	1998–99	2004–05	2012–13
प्लांट लोड फैक्टर	64.6%	74.8%	69.9%

(Source : Central Electricity Authority's yearly reports at website www-cea-nic-in/reports/yearly_report-html)

- नवंबर 2013 की केपीएमजी रिपोर्ट से एक निराशाजनक तस्वीर उभर कर आती है।

(i) वर्ष 2011–12 के अंत में कोयला और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की कमी के कारण कारण बिजली संयंत्रों की 33000 मेगावाट के आसपास की क्षमता अधर में लटक गई जिसकी वजह से इन बिजली संयत्रों में निवेश किये गए 1,00,000 करोड़ अलाभकारी साबित हो गए।

(ii) वर्ष 2011–12 के अंत तक 78 बिजली परियोजनाएं जिनसे 10300 MW बिजली का उत्पादन होना था, पर्यावरण

से जुडी मंजूरी न मिलने कारण लंबित पड़ी हुई थी।

- UPA II ने भारत की विद्युत स्व–पर्याप्तता को आगे बढाने के लिए कुछ नहीं किया। 11 वीं पञ्च–वर्षीय योजना के अंत में भारत को विद्युत क्षेत्र में 13: के अत्याधिक घाटा हुआ है. 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में यही आंकड़ा 12% के स्तर पर था। इसका अर्थ यह हुआ कि, परस्पर सम्बंधित विद्युत की मांग और पूर्ति की शर्तों पर, भारत ने, UPA सरकार के 10 वर्षीय नेतृत्व में बमुश्किल ही कोई प्रगति की है। दिनोंदिन बढ़ती मांग के बीच अनछुई राष्ट्रीय सम्पदा के उपयोग से संभावित विद्युत् सरप्लस वाले देश के बजाय अदूरदर्शी नीतियों ने देश को केवल बढती मांग रोकने कि कोशिश करते रहने पर विवश कर दिया है।
- नेतृत्व और जिम्मेदारी के खराब मानकों के साथ उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न कर पाना, UPA सरकार में स्वीकृत मानक बन गया है. पूर्व निर्धारित 78500 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य कि जगह पहले से ही संशोधित 62000 मेगावाट के बावजूद 11 वीं पञ्च–वर्षीय योजना में मार्च 2012 को, फिर से कम करके 54000 मेगावाट का लक्ष्य जोड़ा गया। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी पूरी आवश्यकता की अपरिहार्यता पर राष्ट्रीय आम सहमति है, तब भी जब यह 70% की एक प्रदर्शन मानक निकलता है। सरकार केवल उन्ही स्थापित संयंत्रों की बात करती है जो कोयले की कमी की वजह से प्रभावित हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 68% ताप विद्युत से पूरा होता है, जबकि इस सरकार ने अपने लालच और भ्रष्टाचार के वजह से रातों रात गायब हो जाने वाले ऑपरेटरों को, जनता कि ऊर्जा जरूरतों को दरकिनार करते हुए रूपया कमाने के लिए लाखों करोड़ के कोयला ब्लॉक देकर भ्रष्टाचार के शर्मनाक आयाम स्थापित किया। खजाने की लागत और लोगों की ऊर्जा जरूरतों पर पैसे बनाने के लिए लाई द्वारा रात ऑपरेटरों को सुगम करने के लिए ताप विद्युत और इस सरकार से मुलाकात कर रहे हैं।
- एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के बावजूद वित्तीय वर्ष 2012 की समाप्ति पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान 4 साल में केवल 3.3% ही कम हो सका।

(ब) घोटालों और पर्यावरण मंत्रालय के सख्त रवैये से खनन क्षेत्र में अव्यवस्था।

कोयला, बॉक्साइट (अल्युमिनियम का उत्पादन में प्रयुक्त) और स्टील हर अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. जो तीन संसाधन हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि यूपीए ने बुनियादी ढांचे के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किस प्रकार से गड़बड़ की है।

(i) कोयला

- भारत का कोयला भंडार 286 अरब टन है, जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। 2012–13 में भारत का कोयला उत्पादन 557000000 टन था और इस अवधि में भारत ने 140 लाख टन कोयला आयत किया. आयातित कोयला महंगा होता है और यह बिजली उत्पादन को भी महंगा बनाता है. वर्ष 2003–04 मांग और आपूर्ति के मध्य मात्र 23.57 लाख टन का अंतर था।

(श्रौत रू 1. आर्थिक सर्वे 2012–13)

1. Coal Ministry's website : www-coal-nic-in/cpdoc-htm
2. Source : Coal Ministry's Annual Report for 2004-05

(ii) बॉक्साइट (अलुमिनियम के उत्पादन में प्रयुक्त)

- भारत 3.5 अरब टन के भंडार के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है। हमारा उत्पादन वास्तव में 2006–07 के 22.6 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2011–12 में 12.8 करोड़ टन तक गिर गया

है। (Source : Indian Bureau of Mines)

(iii) स्टील

भारत दुनिया का सातवाँ लौह अयस्क से समृद्ध और भंडार क्षमता वाला देश हैं, जहाँ 28.5 बिलियन टन लौह अयस्क के सुरक्षित भंडार हैं। वर्ष 2012 में भारत ने, 77 लाख टन स्टील का उत्पादन किया और विडंबना देखिये कि 2012–13 में 7.9 लाख टन स्टील का आयात करना पड़ा। इसके विपरीत चीन ने 716000000 टन स्टील का उत्पादन किया।

- लोह अयस्क (आयरन ओर) निर्यात : वर्ष 2012–13 में भारत ने 18.37 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया।
- हमारे पास इस्पात का सरप्लस उत्पादन हुआ करता था, लेकिन आज हमें स्टील के आयात और लौह अयस्क के निर्यात पर निर्भर हो गए हैं। यह औपनिवेशिक कालखंड के उन दिनों का स्मरण है जब हम कच्चा माल बेचकर तैयार उत्पाद आयत करते थे।

स्टील आयात/निर्यात (आंकड़े लाख टन में)

	2003–04	2011–12
आयात	1.75	6.83
निर्यात	5.21	4.04
अधिशेष/घाटा	+3.45	–2.79

(Source: Annual Report of Steel Ministry वित्त 2004–05 और 2012–13)

यह दुखद व्यथा यहीं समाप्त नहीं होती है। सरकार ने ऐसे लोगों को भी हतोत्साहित किया है जो बड़ी मात्रा में स्टील का उत्पादन करना चाहते हैं. इसलिए हमें देश के विभिन्न भागों में प्रमुख निवेशकों द्वारा मेगा इस्पात संयंत्र बंद करने की घोषणा पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

(क) बंदरगाह

भारत के कुल निर्यात का 90% बंदरगाहों के माध्यम से होता है। पोर्ट उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जहाजों के लिए औसत वापसी समय है जिसमें यह देखा जाता है कि मूल रूप से एक जहाज को लोड या अनलोड होने में कितना समय मिल जाता है और वह जल में परिचालन के लिए कितने समय में स्वतंत्र हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर क्योंकि इससे आयात और निर्यात की लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

भारतीय बंदरगाहों पर औसत वापसी समय (दिनों में)

Year	Turnaround time in days
1996–97	**7.8**
2004–05	**3.41**
2011–12	**5.05**

(Source : Economic Survey वित 1997–98, 2005–06 और 2012–13)

यूपीए सरकार एनडीए द्वारा हासिल दक्षता में बढ़त बनाए नहीं रख सका।

बंदरगाहों के लिए हमारे नौवहन क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए विफलता

- सबसे बड़ी तट श्रंखला होने के बावजूद और प्रमुख शिपिंग मार्गों के पार सेंटर में से एक होने के बाद भी भारत समुद्र आधारित व्यापार के लिए एक सैन्य बेस में खुद को परिवर्तित करने में नाकाम रहा है। भारत में एक भी बंदरगाह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं है। 2011 में दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों की सूची में 30 वां स्थान प्राप्त शंघाई बंदरगाह द्वारा संभाले गए कंटेनर यातायात कि तुलना में भारत यानी श्रछच्ज ने का केवल 13% के कंटेनर यातायात संभाला।

- प्रति जहाज औसत प्रतिक्रम ध्रातिवर्तन काल, हमारे बंदरगाहों की परिचालन क्षमता को दर्शाता है। पर यही औसत समय सं 1991–92 में दर्ज 6–7 दिनों कि तुलना में 1996–97 के बीच 7.8 दिन तक गिर चुका था। NDA के शासन काल में यही औसत प्रभावशाली तरीके से 3.41 दिन तक लाया गया द्य किन्तु UPA II के शासन में बदकिस्मती से यह 5.05 दिन तक बढ़ गया।

- अपर्याप्त बर्थ और रेल सड़क संपर्क के वजह से अभी भी भारतीय बंदरगाह संकटग्रस्त हैं। वर्ष 2012 तक, भारतीय बंदरगाहों के लिए औसत पोत बदलाव का समय प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों में 15–35 घंटे (10 घंटे हांगकांग में) की तुलना में 4 दिन है। 2006 में यही भारत का यही प्रतिवर्तन औसत समय 6 दिन था जिसकी तुलना में पिछले छह वर्षों जिससे फिर पिछले 6 वर्षों के सम्बंधित प्रदर्शन में बहुत कम सुधार दिखा एक औसत 5–6 दिनों पर था।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक, क्षमता निर्माण हेतु निर्धारित 1000 MT के लक्ष्य कि तुलना में भारत द्वारा केवल 690 MT ही इकठ्ठा किया गया।

  टिप्पणीः कांग्रेस नीत UPA सरकार ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक घटक को पिछले 10 वर्षों के नष्ट कर दिया, जिन्हें राजग सरकार ने उसे सुदृढ़ स्थिति में सौंपा था। यह सब सरकार की नीतियों में अपंगता, अप्रभावी नेतृत्व सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलने की वजह से हुआ, जहाँ सरकार की असल कमान कांग्रेस की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संभाल रखी थी।

नोटः उपरोक्त का संक्षिप्त सार अनुबंध में प्रस्तुति के रूप में डाल दिया गया है।

भ्रष्टाचार और लूट

की अंतहीन कहानी

3.0 घोटालों और भ्रष्टाचार की एक अंतहीन गाथा

कांग्रेस नीत UPA सरकार–स्वतंत्रता के बाद अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार।

UPA सरकार के मुख्य घोटाले

2G Spectrum Scam	**1,76,000 Crores**
Coal Scam	**1,86,000 Crores**
CWG Scam	**70,000 Crores**
IGI Airport land grant Scam	**50,000 Crores**
Air India Scam	**25,000 - 30, 000 Crores**
Rotten Food Scam	**58,000 Crores**
Hasan Ali - Money Laundering Scam	**54,000 Crores**
ISRO&Devas Scam	**2,00,000 Crores**
Defense Land Scam	**10,000 Crores**
LIC Housing Loan Scam	**10,000 Crores**

Source: Different media reports, CAG Reports (Figures approximate)

जनता को घोटालों की संख्या और उजागर घोटालों में लूट की राशि जानकर आश्चर्य होगा। इन तमाम घोटालों को अंजाम देने के बाद भी कांग्रेस पार्टी स्वयं को गरीबों की हितेषी और विकास परक बताती है। UPA सरकार के 2004 से शुरू होने वाले प्रमुख घोटालों की सूची इस प्रकार है।

- **नोट के बदले वोट घोटाला**

  नोट के लिए वोट कांड के अंतर्गत 22 जुलाई 2008 को यूपीए ने कथित तौर पर विश्वास मत बचाने के लिए भाजपा सांसदों को रिश्वत दी। जब परमाणु करार पर आगे बढ़ने को इच्छुक सरकार से वाम मोर्चे ने समर्थन वापस ले लिया तब लोकसभा में विश्वास मत को लेकर वोटिंग हुई। नोट के लिए वोट काण्ड ने दिखा दिया कि सदन में जीत सुनिश्चित करने के लिए आमादा कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, इस खुलासे ने सरकार के घोर नैतिक पतन और उसके हास्यास्पद राजनीतिक अवसरवाद दोनों का पर्दाफाश करने के साथ–साथ हमारे संसदीय लोकतंत्र की अछूत परंपराओं को शर्मिंदा व नष्ट किया। इस मामलें में सभी तथ्यों की परख के बाद न्यायालय को भी यह कहना पड़ा कि जो सासंद व्हिसील ब्लोवर का कार्य कर रहे थे। उन्हें प्रताड़ित किया गया और जो वास्तविक आपराधी थे उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की गई।

- **2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला**

  2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भारत के वे राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने उन आवृत्ति लाइसेंस आवंटित करने के बदले में मोबाइल कंपनियों से नियत व संभावित धनराशियों की तुलना में बेहद कम शुल्क वसूला, जिन आवृत्तियों का प्रयोग यह कंपनियां 2 जी स्पेक्ट्रम का निर्माण कर के अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करतीं। 2010 में हुई 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के मूल्य के आधार पर किए गए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक अनुमान के मुताबिक, इस घोटाले में एकत्र हुए धन और एकत्र होने वाले संभावित धन के बीच तकरीबन Rs.1.76 लाख करोड़ है, 2011 में एक संवाददाता

सम्मेलन के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2जी लाइसेंस के वितरण की वजह से सरकार को श्शून्य घाटा (Zero Loss) हुआ था।

लाभ तथा हानि की सभी अटकलों पर लगाम लगाते हुए 2 फरवरी 2012 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुनाया था जोकि सीधे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम के आवंटन को 'असंवैधानिक और मनमाना' बताया तथा ए राजा व 2जी घोटाले मामले के अन्य आरोपियों के कार्यकाल के दौरान 2008 में जारी किए गए सभी 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया। अदालत ने आगे कहा कि ए राजा 'सरकारी खजाने की कीमत पर कुछ कंपनियों के पक्ष में' कुछ करना चाहते थे, तथा उन्होंने 'वस्तुतः महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति को ही उपहार में दे दिया' आगे चलकर 3 अगस्त 2012 को कपिल सिब्बल का 'शून्य घाटा सिद्धांत' भी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत सरकार ने 5 मेगाहर्ट्ज 2 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य को संशोधित कर के 140 अरब डॉलर कर दिया जिसके अनुसार स्पेक्ट्रम का मूल्य तकरीबन 28 अरब रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज बैठता है जोकि सीएजी के प्रति मेगाहर्ट्ज 33.5 रुपए के अनुमान के आस–पास ही है।

इस पूरे घोटालें में डॉ. मनमोहन सिंह अपने गम्भीर दायित्व से बच नही सकते क्योंकि उनके और श्री राजा के बीच हुए पत्रचार से यह स्पष्ट है कि इस भयंकर घोटाले की जानकारी के बावजूद वे शांत रहे और इसको रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नही किया। वही दूसरी ओर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए–राजा ने बार बार यह कहा है कि उन्होंने सबकुछ प्रधानमंत्री के सहमति से किया। यह आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े घोटाले में सीबीआई ने न प्रधानमंत्री और न ही उनके कार्यालय के किसी पदाधिकारी से पूछताछ किया जबकि 1.76 लाख करोड़ जनता के पैसो की लूट हुई।

- **स्विस काला धन घोटाला**

  विभिन्न विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार भारत के 22.5 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा पड़े हैं। यह दुनिया के 180 देशों में से किसी भी देश की उसकी सीमा से बाहर पड़ी उच्चतम राशि है। भारत काले धन के मामले में सबसे आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस तथा कई अन्य देशों ने स्विस बैंक से अपना काला धन वापस लाने व उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए स्विस सरकार के साथ कई समझौते किए। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस तरह की कार्रवाई को यथासंभव टाला व इसमें देरी की। अमेरिका और अन्य देशों ने स्विस बैंकों से अपने नागरिकों का धन वापस निकालना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में छिपा हुआ पैसा करापवंचन से ही जमा किया गया है। हसन अली खान नाम के एक कुख्यात अवैध हवाला आपराधिक व्यापारी का तकरीबन 8 अरब डॉलर काला धन स्विस बैंक खातों में जमा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर इस पूरे मामले में एक 'आपराधिक साजिश' का हिस्सा होने का आरोप लगाया। जिसमें काफी विश्वसनीयता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी विदेश से काला धन लाने में कभी गम्भीर नही रही है, क्योंकि उन तत्वों को कांग्रेस का खुला प्रश्रय मिलता है, जिससे कॉंग्रेस बेनकाब हो सकती है।

  पिछले लोकसभा चुनाव में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ा था। ग्लोबल फाइनेंनसियल इन्टिग्रीटी के 2011 के रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के अवैध धन की राशि 462 बिलियन डालर के आसपास है। वियतनाम और दक्षिण कोरिया ऐसे छोटे देश भी विदेशों में जमा कालाधन को लाने के लिए काफी सक्रिय है। जबकि संप्रग सरकार की सक्रियता मात्र सांकेतिक पत्र लिखने तक ही सीमित है।

- **जल विद्युत परियोजना घोटाला**
  - 21 वीं सदी की शुरुआत में, पूर्वोत्तर अरुणाचल को 'भारत के भविष्य के पावर हाउस' के रूप में पहचाना गया था। इस अवधारणा को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और देश के हित के लिए क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों यानी नदियों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था।
  - इस आधार पर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी ने 2001 के अपने आरंभिक अध्ययन के आधार पर ब्रह्मपुत्र बेसिन में 63328 मेगावाट के क्षमता वाले 168 प्रोजेक्ट को चिहिन्त किया जिसे 2002 में मुम्बई के नार्थ ईस्ट बिजनेस समिट में प्रस्तुत किया गया। श्री वाजपेयी की योजना थी कि उतर पूर्व राज्यों के प्रा.तिक क्षमताओं का सदुपयोग इस संतुलित तरीके से हो की इसका लाभ उस इलाके के अतिरिक्त शेष देश को भी हो सके।
  - इस बड़ी सोच को 2004 में सरकार में आने के बाद कॉंग्रेस ने भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा माध्यम बना लिया। मात्र दो वर्षों में 137 MOU/MOA समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और फर्जी अनुभवहीन और रातों रात बनी अयोग्य कम्पनीयों का हजारों करोड़ के ठेके दिए गए और भारी लूट हुई।

➢ **आदर्श हाउसिंग सोसायटी**

आदर्श हाउसिंग सोसायटी मुंबई में एक सहकारी समिति है। इस घोटाले की जड़ें फरवरी, 2002 से शुरू होती हैं जब 'रक्षा सेवा में सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण' के लिए मुंबई के मध्य में एक आवासीय परिसर का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भूमि आवंटित करने संबंधी एक अनुरोध भेजा गया था. उसके बाद एक लंबी अवधि के दौरान शीर्ष राजनेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर कई नियमों को बुरी तरह तोड़–मरोड़ कर व कानून को ताक पर रख कर विशेष रूप से कम कीमतों पर आवंटित की गई इस प्रतिष्ठित संपत्ति में पहले भवनों का निर्माण किया और फिर उन्हें स्वयं अपने ही नाम पर आवंटित कर लिया। 2011 में सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के प्रकरण से पता चलता है कि कैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे चुनिंदा अधिकारियों के एक समूह प्रमुख सरकारी जमीन जोकि एक सार्वजनिक संपत्ति है को हड़पने के क्रम में नियमों और कानूनों को पूरी तरह पलट सकते हैं। 2013 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने इस घोटाले में अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे व शिवाजी राव नीलांगेकर पाटिल समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियोंय राजेश टोपे और सुनील ततकरे समेत 2 पूर्व शहरी विकास मंत्रियों तथा 12 शीर्ष नौकरशाहों को व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न अवैध कार्य करने का दोषी ठहराया। इस घोटाले में महाराष्ट्र के तत्कालीन अशोक चव्हाण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

- **ISRO's commercial arm Antrix Corp and Devas Multimedia**

यह कथित घोटाला इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्प और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए एक सौदे से संबंधित है। इसरो पर दुर्लभ एस–बैंड स्पेक्ट्रम में से 70 मेगाहर्टज, देवास को 20 साल की अवधि के लिए आवंटन का आरोप है। इस मामले में सीएजी की सतर्कता इसलिए बढ़ी क्योंकि ठेके की शर्तों में इसरो ने स्पेक्ट्रम को आगे पट्टे पर देने के लिए देवास मल्टीमीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा था, जिसका अर्थ है कि कंपनी सब–लीज कर अपने विशेषाधिकार का दुरूपयोग कर भारी मात्रा में कमाई कर सकती थी।

सीएजी को इस पूरे एस–बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में एक बड़ा घोटाला होने का संदेह है और कथित तौर पर वह इस घोटाले में 2 लाख रु करोड़ के घाटे की जांच कर रही है. इसरो और देवास मल्टीमीडिया के बीच इस सौदे की वजह से सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है. इस सौदे

में जीसैट–6 और जीसैट–6A नाम के दो संचार उपग्रह भी शामिल हैं और 10 ट्रांसपोंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा. अंतरिक्ष विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है. यह घोटाला सिर्फ भारत सरकार के खजाने को हुआ राजस्व का नुकसान भर नहीं है, यह एक अत्यधिक दुर्लभ स्पेक्ट्रम की क्षति है जोकि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्ति है।

यहां तक कि 1.76 लाख करोड़ रुपए का 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला और 1.85 लाख करोड़ रुपए का घोटाला एस–बैंड घोटाले की तुलना में छोटा लग रहा है। देश में भारी विरोध, अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण सरकार को इस पूरे करारनामें का रद्द करना पड़ा।

- **हेलीकाप्टर रिश्वत कांड**

  कई भारतीय राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों पर ऑगस्टा वेस्टलैंड नामक कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है ताकि उसे 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड AW101 हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए भारतीय अनुबंध प्राप्त हो सके। यह हेलीकाप्टरों अति महत्वपूर्ण व्येक्तियों व राज्य संबंधी अन्य कार्यों के लिए लिए जाने थे। इटली में जाँच के दौरान अभियोजकों के पास कॉंग्रेस के कई शीर्षस्थ नेताओं की संलिप्तता की चर्चा तथ्यों के आधार पर आई है।

  25 मार्च 2013 को भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि 'हाँ, हेलिकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और रिश्वत ली गई है तथा सीबीआई बहुत सख्ती से इस मामले की जांच कर रही है।'

- **रेलवे रिश्वत घोटाला**

  3 मई 2013 को चंडीगढ़ में भारतीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भतीजे विजय सिंगला को भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार की ओर से नारायण राव मंजूनाथ और संदीप गोयल द्वारा विदेशी मुद्रा में दी जा रही 90 लाख रुपये की रिश्वत इस उद्देश्य से स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि इसके एवज में महेश कुमार को रेलवे बोर्ड पर एक उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सके। कथित तौर पर घोटाले में शामिल मंत्री ने 10 मई 2013 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि सीबीआई ने इस मामले की जाँच करते हुए श्री पवन बंसल को अपराधी के वजाय गवाह बनाया जबकि उनका भतीजा जिसके खिलाफ उनके विना पर घूस लेने का आरोप है, इस मामलें का एक मुख्य अभियुक्त है।

- **कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट**

  कोयला घोटाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा देश के कोयले के भंडार को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं व निजी कंपनियों को आवंटन के विषय में किया गया एक राजनीतिक घोटाला है। 27 अगस्त 2012 को संसद में पेश कैग की अंतिम रिपोर्ट में इस घोटाला का आंकड़ा तकरीबन 185,591 करोड़ आंका गया था, तथा सीएजी की रिपोर्ट का सार यह है कि काम्पेटिटिव बीडिंग की प्रक्रिया को अपनाने में जानबूझ कर देरी की गई और बड़ी संख्या में कोयला खादानें अयोग्य कम्पनीयों को सारे मानकों को दरकिनार करके दी गई। भाजपा की शिकायत के जवाब में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया।

  सीबीआई ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक दर्जन से अधिक भारतीय कंपनियों के नाम शामिल किए हैं। इस रिपोर्ट में उन पर अपनी परिसंपत्तियों से अधिक घोषित करने, पूर्व में किए गए कोयला आवंटन का खुलासा न

करने तथा आवंटित की गई कोयला खदानों को विकसित करने के बजाए उन्हें छुपाने–दबाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में भयंकर भ्रष्टाचार और घूसखोरी का मामला सामने आया है। कई खादानें कांग्रेस के नेताओं के नजदीकी लोगों देने का आरोप है।

नोटः कोयला घोटाला जिस अवधि में हुआ उसमें अधिकांश समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ ही साथ कोयला मंत्री भी थे, किन्तु उनकी स्वयं की भूमिका की जाँच अभी तक नही हुई है।

26 अप्रैल 2013 को सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत कर के कहा कि जांच एजेंसी द्वारा तैयार कोयला घोटाला स्थिति रिपोर्ट को 8 मार्च 2013 को अदालत को पेश करने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ''इच्छा के अनुसार'' स्वयं कानून मंत्री के साथ–साथ प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों तथा कोयला मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील द्वारा किए गए दावे के विपरीत है कि अदालत को पेश करने से पहले इस रिपोर्ट को सरकार के किसी भी सदस्य के साथ साझा नहीं किया गया था। 29 अप्रैल 2013 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उसकी मूल रिपोर्ट को सरकार द्वारा 20% तक बदल गया था. इसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में इस्तीफा दे दिया।

- **एलआईसी हाउसिंग लोन घोटाला**

  विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष व मध्यम प्रबंधन अधिकारी निजी वित्तीय कंपनी से रिश्वत प्राप्त कर रहे थे तथा इसके बदले में कॉर्पोरेट ऋण और वित्तीय संस्थानों से अन्य सुविधाओं के लिए मध्यस्थों और सहायकों के रूप में काम कर रहे थे। इस घोटाले में हजारों करोड़ रुपये गैर–जिम्मेदार तरीके से ऋण के रूप में वितरित किए गए।

  सीबीआई ने आरोप लगाया कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी व्यापार ऋण के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हुए निजी वित्तीय सेवा कंपनी से रिश्वत प्राप्त कर रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने अन्य अनियमितताएं बरतने के साथ–साथ इस तरह की मंजूरी के लिए अनिवार्य शर्तों को दरकिनार करते हुए बिल्डर्स व रियल्टी डेवलपर्स को बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट ऋण मंजूर किए।

- **एयर इंडिया घोटाला**

  एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों ही वर्ष 2003–04 तक मुनाफा प्रदान करने वाले उपक्रम थे। लेकिन UPA सरकार के आपराधिक कुप्रबंधन ने राष्ट्रीय विमान सेवा पर 50,000 करोड़ रूपये के नए विमानों की खरीद का बोझ लाद दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। लाभ प्रदान करने वाले वायु मार्गों पर सेवाएं बंद कर दी गईं, उन्हें निजी विमान सेवाओं को दे दिया गया। जिन अधिकारियों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई उन्हें हटा दिया गया। वित्त वर्ष 2012–13 में एयर इंडिया 3159 करोड़ रूपये के घाटे में हैं। यह हजारों करोड़ रूपये का बोझ आम करदाता की जेब पर पड़ा है, इसके लिए UPA सरकार जिम्मेदार है। तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में विमान खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया, सरकार का यह कदम सरकारी खजाने के लिए वित्तीय तनाव का कारण बना। यह पूरा घोटाला 25,000–30,000 करोड़ का अनुमानित है।

- **खाद्यान्न के सड़ने का घोटाले**

  प्रति वर्ष देश के तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए खाद्यान्न सड़ने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। सरकार इसके कारण के तौर पर पर्याप्त जगह की कमी का हवाला देती है लेकिन कोई भी नया भंडारगृह निर्माण नहीं करती

है। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब लोगों को निरू शुल्क भोजन वितरण का आदेश दिया है। सड़े अनाज को शराब माफियाओं को 62 पैसे प्रति किलो की दर से बेच दिया गया था। ऐसे समय ये भयंकर कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार है जब एक ओर मँहगाई के बोझ से लाखों गरीब आदमी भूखमरी में जीने को मजबूर है वही अनाज गोदामों में सड़ता है।

- **बढ़ती कीमतों – मुद्रास्फीति/महंगाई घोटाला**

  24 महीनों से भी अधिक समय से पूरे देश में खाद्य कीमतों में भयानक इजाफा हुआ है। पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति दो अंकों में रही है। इस मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति का मुख्य कारण यूपीए सरकार की गलत नीतियां, निर्णयों तथा भ्रष्ट प्रशासन रहा है। जहां एक ओर गरीब आदमी को अपना भोजन नहीं मिल पा रहा है वहीं किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ओर रिकॉर्ड फसल उत्पादन की बात कही जाती है और दूसरी ओर इतनी मँहगाई। मँहगाई के सम्बन्ध में कई स्तरों पर काफी अनियमितता और घोटाला है।

- **केजी बेसिन तेल घोटाला**

  भारत के महालेखाकार ने के जी बेसिन और अन्य निजी तेल कुओं से संबन्धित रिपोर्ट में गैसों के मूल्यों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गम्भीर अनियमितताए पायी है। कांग्रेस सरकार के कई पेट्रोलियम मंत्रियों के भूमिका के संबंध में भी कई गम्भीर सवाल उठे है। संसद की वित स्थायी समीति जिसके अध्यक्ष भाजपा के यशवन्त सिन्हा है ने अपनी रिपोर्ट में पूरे गैस कीमत के मामलें पर उपभोक्ताओं के हित में पुर्नविचार करने की गंभीर अनुशंसा की है।

- **चावल निर्यात घोटाला**

  यूपीए सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात में गंभीर खामियों को स्वीकार किया है और माना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) ने गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल को सामान्य चावल के नाम पर निर्यात किया गया था। इस चावल को पिछड़े अफ्रीकी देशों को निर्यात किया और बदले में पिछड़े अफ्रीकी देशों ने इसी चावल को यूरोप के लिए भेज दिया और ऊंची कीमत पर बेच दिया। जब इस सैंकड़ों करोड़ के घोटाले का पता लगा तो सरकार ने अपनी खामियों को स्वीकार किया और संदिग्ध फर्मों की जांच के लिए सीवीसी/सीएजी को निर्देश दिया तथा जिन्हें दोषी पाया गया जांच के बाद उन फर्मों को काली सूची में भी डाला गया। यह पूरा घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ और देश में मुखर आवाज उठने के कारण कारवाई करने पर मजबूर होना पड़ा।

- **रॉबर्ट वाड्रा भूमि घोटाले**

  राबर्ट वाड्रा जमीन घोटाला सरकारी संरक्षण में किए गए भयंकर घोटाले का एक ज्वलंत नमूना है। राबर्ट वाड्रा और उनके पॉकेट कम्पनियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में किसानों की जमीन बड़ी मात्रा में खरीदी, सरकारी सहयोग से इसका लैण्ड–यूज तेजी से बदला गया और बाद में ऊचे दर पर उन जमीनों को बिल्डर और उनके नुमाइनदो का बेच दिया गया जिसके कारण राबर्ट वाड्रा की कम्पनियों को करोड़ो का फायदा हुआ। इस पूरी प्रकिया में हरियाणा और राजस्थान की कॉंग्रेस सरकारों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और कई ईमानदार पदाधिकारी जो इन अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे उन्हें दण्डित भी किया।

- **इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली की सार्वजनिक निजी भागीदारी के कार्यान्वयन में भूमि घोटाला**

  सीएजी की 2012–13 की रिपोर्ट संख्या 5 में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली (नागर विमानन मंत्रालय) आईजीआई हवाई अड्डे के विकास कार्यान्वयन के निष्पादन में रियायत देने में भारी अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि किस प्रकार से निजी डेवलपर को केवल 1,813 करोड़ रुपये के इक्विटी योगदान से 24000 करोड़ के भूमि पर वाणिज्यिक अधिकार दे दिए गए जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत मात्र 12,857 करोड़ रुपए की थी और इस परियोजना के माध्यम से संभावित कमाई 163,557 करोड़ रूपये है। इस पूरे मामलें में मोटे रूप में भी लगभग 50,000 करोड़ की अनियमिततओं की स्पष्ट आशंका है।

- **रक्षा भूमि घोटाला**

  देश के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर रक्षा भूमि को बड़े पैमाने पर अनियमितताओं एवं गैर पारदर्शी तरीके से बिल्डरों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सौंप दिया गया। यह मुद्दा सार्वजनिक है, संसद में भी इस विषय को लेकर प्रश्न उठाये गए हैं। विपक्षी दलों के दवाब में सरकार ने बेशक कुछ मामलों में जांच के आदेश दे दिए हों। लेकिन यह घोटाला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह भूमि घोटाला लगभग 10,000 करोड़ रूपये का है।

- **ऋण माफी योजना में घोटाला**

  गरीब किसानों के हित के लिए बहुप्रचारित ऋण माफी योजना में भी CAG ने भारी अनियमितताएं दर्ज की हैं। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर कुपात्रों को इस योजना के माध्यम से पैसा बांटा गया, जिसे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

  घोटालों की उल्लेखित सूची महज कुछ उदहारण भर हैं। अभी भी अन्य अनियमितताओं की तमाम खबरें सुनने में आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA के सरकार आजाद भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है।

राष्ट्रीय सुरक्षा
की गंभीर चुनौतियाँ

4.0 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ

4.1 बाहरी खतराः सरकार भारत तिब्बत सीमा पर चीन की सशक्त व चिन्ताजनक उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए एक प्रभावी नीति अपनाने या पर्याप्त रूप से सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने में नाकाम रही है।

- 1950 में तिब्बत के अपने कब्जे के बाद से, चीन ने भारत तिब्बत सीमा पर भारी सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया है। 2005 के बाद से तिब्बत में चीनी सैन्य बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है तथा भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक पक्की सड़कों को बना दिया गया है। तिब्बत में चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को 2008 में गोर्मू–ल्हासा रेलवे लाइन के परिचालन के साथ एक प्रमुख बढ़त हासिल हुई जो कि भविष्य में भारत के प्रति चीन के इरादों में कड़वाहट के बढ़ने की स्थिति में उत्तरी सीमाओं के पार से भारत के लिए बड़े सैन्य खतरे का कारण बन सकता है। बुनियादी ढांचे और सैन्य संसाधनों में लगातार बढ़ती वृद्धि के चलते चीनी सैनिक भारत के प्रति हाल के वर्षों में अधिक से अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं और पिछले कुछ समय में वे भारतीय क्षेत्र में बार–बार घुसपैठ की घटनाओं को दोहराते रहे हैं। मात्र पिछले दो वर्षों में ही, चीनी सैनिकों द्वारा सीमा उल्लंघन की 500 से अधिक घटनाओं को सूचित किया गया है। UPA सरकार सही ढंग से इन घटनाओं के सैन्य प्रभाव का आकलन तथा भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने में बुरी तरह विफल रही है जो कि निम्न रूप में परिलक्षित होता हैः–
- यह भारत तिब्बत सीमा के हमारे पक्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास के काम में तेजी लाने में असफल रही। वर्ष 2022 तक पूरी होने वाली सीमा सड़क की 503 परियोजनाओं में से केवल 17 अब तक पूरी हुई हैं और वर्तमान में काम सिर्फ 50 परियोजनाओं पर चल रहा है। 29 जून 2006 को सीसीएस ने 2012 तक भारत तिब्बत सीमा पर 73 सीमा सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिया था. 3,505 किमी की कुल लंबाई वाली इन सड़कों में से 15 मार्च 2013 तक केवल 527 किमी या निर्धारित सड़कों करीब 31% ही पूरा किया जा सका। सरकार तिब्बत की सीमा से लगे राज्यों में सैन्य और नागरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पर निगाह रखने में, तथा इन प्रक्रियाओं हेतु भूमि अधिग्रहण व पर्यावरणीय मंजूरी आदि जैसी औपचारिकताओं में शीघ्रता लाने में नाकाम रही है जिससे बुनियादी ढांचे के विकास की इन परियोजनाओं में भारी विलंब हुआ है।
- देश कि उत्तरी सीमा पर बने खतरे की गंभीरता का आकलन करने व उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना के लिए मंजूरी देने में इस सरकार ने बेहद ढुल–मुल रवैया अपनाया, तथा इसका उदासीन रवैया और सामरिक दृष्टि की कमी इससे साबित होती है कि किस प्रकार इस प्रस्ताव पर 2011 में वित्त मंत्रालय ने यह संदेह उठाते हुए सवालिया निशान लगाया था कि क्या कभी भारत और चीन में युद्ध हो भी सकता है? चीनी खतरे के प्रति आगाह होने में यूपीए सरकार को पूरे आठ साल लगे, तथा अंततः यह स्ट्राइक कोर नवंबर 2013 में जारी किया गया।
- सरकार ने चीनी सैनिकों द्वारा बार–बार सीमा के उल्लंघन करने की घटनाओं को कम करके पेश किया व देश को यह कहते हुए गुमराह किया कि यह सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की भिन्न परिभाषाओं के कारण उपजी गलतफहमी ही है। सरकार द्वारा अभी तक यह खुलासा भी नहीं किया गया है कि चीन के साथ सीमा वार्ता या वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण के संबंध में क्या प्रगति हुई है।
- सीमा प्रबन्धन और नियंत्रण रेखा के सम्बन्ध में रक्षा और गृह मंत्रालय के बीच समन्वय के अभाव के कारण काफी कठिनाई हो रही है। साथ ही, सरकार द्वारा भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई की स्वतंत्रता बाधित करने और 23

अक्टूबर, 2013 को बीजिंग में भारत व चीन के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए सीमा रक्षा सहयोग समझौते (BDCA) के कुछ प्रावधानों के चलते चीनी घुसपैठ से .ढ़तापूर्वक व प्रभावी तरीके से निपटने में भारतीय सैनिक अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित हो रहे हैं।

- सरकार ने चीनी सैनिकों द्वारा बार–बार सीमा के उल्लंघन करने की घटनाओं को कम करके पेश किया व देश को यह कहते हुए गुमराह किया कि यह सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की भिन्न परिभाषाओं के कारण उपजी गलतफहमी ही है। सरकार द्वारा अभी तक यह खुलासा भी नहीं किया गया है कि चीन के साथ सीमा वार्ता या वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण के संबंध में क्या प्रगति हुई है।
- हाल के वर्षों में, परमाणु, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में चीन तथा पाकिस्तान के मध्य गुप्त मिलीभगत व सहयोग में लगातार अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली है। यह मिलीभगत पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों की क्षमता में खतरनाक हद तक इजाफा करती है। सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र या POK) में चीनी सैनिकों की मौजूदगी के मुद्दे पर पाकिस्तान व चीन दोनों से दृढ़ता से विरोध जताने में नाकामयाब रही है। इस क्षेत्र में परिवहन गलियारे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से ग्वादर बंदरगाह के रास्ते अरब सागर के गर्म पानी तक चीन की पहुंच और अधिक आसान होगी। एक ऐसे क्षेत्र में जोकि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत द्वारा एक मजबूत प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने के साथ–साथ भारत को घेरने की चीन की क्षमता को मजबूत किया है। चीन भी संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों पर सहयोगी रवैया दिखाते हुए उस के बचाव में आ चुका है।
- सरकार द्वारा लगातार लचर और कमजोर प्रतिक्रियाओं से उत्साहित होकर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के इर्द–गिर्द विवादित क्षेत्रों की संख्या में लगातार विस्तार कर रहा है और जो क्षेत्र दोनों पक्षों की ओर से अभी तक विवादित रूप में पारस्परिक रूप से मान्य नहीं कर रहे हैं, उनमें लगातार सीमा उल्लंघन के लिए कदम उठा रहा है। यहां तक कि 2003 में सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत के हिस्से के रूप में मान्यता देने के बावजूद चीन ने 2008 में सिक्किम में क्षेत्र के एक हिस्से के विवादित होने का दावा किया। सीमा विवाद पर चीन की बढ़ती बदनीयती और आक्रामकता का प्रमाण उसके द्वारा पहले तवांग पर किए जा रहे अपने दावे को पूरे अरुणाचल प्रदेश तक आगे बढ़ाने, सीमा विवाद को एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत करने, जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता नहीं देने तथा अरुणांचल प्रदेश व जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करने से मिलता है.
- यह वास्तव में विडंबना ही है कि एक ओर चीन से बढ़ते आर्थिक संबंधों (हालांकि वे अभी भी एकांगी रूप से चीन के ही पक्ष में जाते हैं) और पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किए गए चीन के कई दौरों के बावजूद, भारत सरकार चीन से इन मुद्दों पर अपने मत के अनुकूल मान्यता प्राप्त करने की तलाश में नाकाम रही है। 2005, 2012 और 2013 में किए गए कई विश्वास वर्धक प्रयास तथा सीमा रक्षा समझौते भी चीनी सैनिकों द्वारा सीमा के उल्लंघनों की संख्या में कमी लाने में नाकाम रहे हैं। सरकार लगातार वास्तविकता से भागने का प्रयास कर रही है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता कर रही है. सीमावर्ती इलाकों के बुनियादी ढांचे के विकास में धीमी प्रगति भी वहां रहने वाले लोगों के मन में चीनी घुसपैठ के खिलाफ उनकी रक्षा करने और उनकी आर्थिक भलाई के लिए अवसर उपलब्ध कराने की भारत की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर रही है।

4.2 आंतरिक सुरक्षाः

आंतरिक सुरक्षा का माहौल दिनोदिन बद से बदतर होता जा रहा है. शहरों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अपराध का बढ़ता ग्राफ लोगों के बीच जबरदस्त असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है। देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में भी स्पष्ट वृद्धि हुई है। 2012 में इस तरह की 640 घटनाओं में 93 लोगों की जान चली गई और 2067 से अधिक घायल हो गए थे। वहीं 2013 में अगस्त माह तक 479 घटनाओं में 107 लोग मारे गए और 1647 घायल हो गए थे।

- पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन में हुई धीमी प्रगति से भारत में पुलिस की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश और अपने ही किए वादों के बावजूद, सरकार पुलिस नियंत्रण को पुलिस प्रशासन से अलग करने में नाकाम रही है। पुलिस और सिविल सेवा के अधिकारियों के काम में हो रहे राजनीतिक दखल व दबाव से वे दंगाइयों, अपराधियों और राजनीतिक संरक्षण का आनंद ले रहे संगठित माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम हो रहे है। उत्तर प्रदेश में ही दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में या कुछ जघन्य अपराधों के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर डाले गए राजनीतिक दबाव ने अंततः किस प्रकार पूरे राज्य को अगस्त 2013 में एक भयानक सांप्रदायिक अग्निकाण्ड में झोंक दिया, यह इस प्रवृत्ति के ही कुछ हालिया उदाहरण हैं।
- पुलिस आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण की गति को तेज करने में असमर्थता सरकार की एक और विफलता है। देश में 12,000 पुलिस स्टेशन अभी भी पुरातन व्यवस्थाओं के तहत और अपर्याप्त सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। कांस्टेबल के पद पर कमियों को दूर करने और पुलिस की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयास भी निराशाजनक हैं।
- 72 लाख से अधिक आपराधिक मामले देश भर की अदालतों में लंबित हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर लोगों का विश्वास अपराधियों के मनोबल को कुचलने का कार्य करता है। सरकार को न्यायपालिका के साथ अधिक सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करते हुए विशेष रूप से जघन्य अपराधों के कृत्यों में न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत से उन्हें अवगत कराना चाहिए था तथा साथ ही बेहतर तरीके से त्वरित न्याय प्रदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस करना चाहिए था।
- वोट बैंक की राजनीति की संकीर्ण विचारधारा, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और उन में प्रताड़ित व उत्पीडित होने की भावना भरना, एक खास समुदाय को खुश करने के क्रम में कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई हिंसा और जघन्य अपराधों के कृत्यों को संरक्षण देना, सांप्रदायिक आधार पर मुफ्त सौगातें बांटने और नौकरियों में आरक्षण देने जैसे कृत्य वह कारक हैं जो समाज को विभाजित कर रहे हैं और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं।
- सरकार भारत में हो रहे अवैध घुसपैठियों के सतत प्रवाह की रोकथाम करने में बुरी तरह विफल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारत के खिलाफ एक युद्ध के रूप में यह घोषित कर रखा है। वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार ने भारत के मतदाता पहचान पत्र अवैध रूप से हासिल करने वाले और देश भर में रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर चुके घुसपैठियों को रोकने में एक सोची–समझी उदासीनता दिखाई है। 2003 में खुफिया ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के मुताबिक भारत में लगभग 1.6 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। माना जाता है कि पिछले एक दशक में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों का घनत्व सबसे अधिक है। यहां तक कि असम के 27

जिलों में से 11 में अवैध आप्रवासी बहुसंख्यक आबादी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2005 में अवैध प्रवासी निर्धारण अधिनियम (आईएमडीटी) लागू किए जाने के बाद भी सरकार घुसपैठियों को देश से निर्वासित करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। बांग्लादेश से अवैध आव्रजन भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं का एक प्रमुख विषय है और यह आतंकवादी समूहों को भी उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार आधार प्रदान करता है।

- माफिया और आपराधिक संगठनों को राजनैतिक संरक्षण मिलने, पुलिस के रोजमर्रा के काम में अत्यधिक हस्तक्षेप और आपराधिक न्याय प्रणाली की लंबी प्रक्रियाओं ने अपराधियों का हौसला बढ़ाया और अधिक अपराध को बढ़ावा दिया है। देश भर में व्याप्त अराजकता ने शांति के माहौल को बिगड़ दिया है। लोगों को न केवल अपनी आजीविका को बनाए रखने बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने में योगदान देने के लिए उपयुक्त व सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है।
- सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर में हिंसा के स्तर में भारी गिरावट के बावजूद सरकार उनकी सफलता के आधार पर नए कदम उठाते हुए लोगों को इस शांति से लाभ का हस्तांतरण करने में विफल रही है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार ने जबरन वसूली विद्रोहियों की गतिविधियों को बाधित करने और लोगों के लिए आर्थिक विस्तार अवसरों को बढ़ाने में अपने प्रयासों को मंदा ही रखा है। मुसीबत के प्रारंभिक लक्षणों के बावजूद, जुलाई 2012 में सरकार निचले असम के जिलों में दो जातीय समुदायों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफल रही जिसमें लगभग 100 लोगों की हत्या हुई तथा हजारों अन्य बेघर हो गए। हिंसा के इस चक्र के परिणाम दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिले जहां उन राज्यों में काम कर रहे पूर्वोत्तर के लोगों को धमकियां दी गईं। सरकार इस हिंसा को भड़काने में विदेशी कोण का पता लगाने में भी विफल रही, क्योंकि इन लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले नफरत भरे संदेशों और प्रचार वीडियो की एक बड़ी संख्या को खाड़ी देशों से परिचालित किया जा रहा था।
- वहीं जम्मू और कश्मीर में 2008–10 के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं 150 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि कई हजार अन्य घायल हो गए. करीब 3,000 पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी भी इन घटनाओं में घायल हुए लगातार विरोध प्रदर्शनों और बंदी से सार्वजनिक संपत्ति का व्यापक विनाश हुआ तथा कार्य दिवसों और आर्थिक गतिविधियों का भी काफी नुकसान हुआ जिससे लोगों को बड़ी मात्रा में वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ा, तथा इन घटनाओं से जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विभेद की खाई भी चौड़ी हो गई। जम्मू कश्मीर में सत्ताधीन राज्य सरकार के साथ केन्द्र में गठबंधन में होने के बावजूद केन्द्र सरकार उस पर इस बात के लिए दबाव डालने में विफल रही कि वह राज्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए वास्तविक शक्तियों का विकास करे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के स्थाई अवसर पैदा करने में नाकामी राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक बड़ी असफलता है और यह भारत के प्रति राज्य की आबादी के मन में अलगाव की भावना को मजबूत करती है।
- अक्तूबर 2004 में प्रधानमंत्री ने देश के लिए सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में वामपंथी उग्रवाद को चिन्हित व सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। लेकिन इस बेहद गंभीर मसले पर सरकार की प्रतिक्रिया खतरे की गंभीरता और परिमाण के अनुरूप नहीं है। वामपंथी उग्रवाद ने पिछले एक दशक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर में हुई नागरिकों और सुरक्षा बलों की कुल मौतों से अधिक लोगों की जान ली है. 2005 के बाद

से 6,000 से अधिक नागरिक और सुरक्षा बल कर्मी वामपंथी उग्रवाद के हमलों में मारे जा चुके हैं। भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में लगभग 170 जिले वामपंथी उग्रवाद से कुछ हद तक प्रभावित हैं।

- 1976 के वन अधिकार अधिनियम और 1996 के पेसा को पूर्णता से लागू कर जनजातीय आबादी के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जाए।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के हर नुक्कड़ और कोने में बुनियादी ढांचे का विकास बढ़ाया जाए। इन क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी इंतजाम मजबूत करने से पहले विकास प्रदान करने की रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले क्योंकि विकास राशि को चरमपंथियों द्वारा लूट लिया जाता था जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता था। लोगों को सुरक्षा का भाव प्रदान किए बिना कोई विकास संभव नहीं है।
- वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक समग्र और संयुक्त रणनीति तैयार की जाए। यह समस्या केवल प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) भेजने से हल नहीं की जा सकती। समस्या के भौगोलिक प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार प्रभावी ढंग से चरमपंथियों की आवाजाही पर सख्त रोकथाम लगाने के लिए एक एकीकृत रणनीति तैयार करने में विफल रही है। माओवादियों के खिलाफ लड़ाई पर अत्यधिक नकारात्मक असर इसलिए भी पड़ा क्योंकि जब–जब गृह मंत्री ने सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की तब–तब श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में शामिल कुछ तत्वों ने भूमिगत माओवादियों का हर संभव वैचारिक बचाव किया। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं कांग्रेस के मुखपत्र 'सन्देश' में छद्म बुद्धिजीवियों की भाषा में बोलते हुए लिखा था कि किस प्रकार इस मुद्दे को अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वामपंथी उग्रवाद का असर अंतर्राज्यीय स्तर तक होता है और अलग–अलग राज्यों में अपने बूते पर इस समस्या से निपटने के लिए क्षमता और विशेषज्ञता की कमी है।
- एक प्रभावी परिचालन रणनीति बनाई जानी चाहिए जो चरमपंथियों की शक्ति को बाधित कर सकती हो। वामपंथी उग्रवाद के प्रति रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने से उन की गतिविधियों पर पर्याप्त रोकथाम नहीं हो पाई है जिसके कारण वे भारत के अंदरूरी क्षेत्रों में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। सरकार के पास वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने में लगे हुए CAPFs और विशेष पुलिस बलों के प्रशिक्षण व उपकरण आदि को पुनः उन्मुख करने के लिए 10 साल की लंबी अवधि थी, लेकिन अभी तक यह समस्या का स्थायी समाधान खोजने के बजाय स्थिति को संभालने के उद्देश्य से मात्र एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण ही अपनाती आ रही है। नतीजतन, चरमपंथियों ने इतनी ताकत हासिल कर ली है और अपनी रणनीति को इतना मजबूत कर लिया है कि वे अपने इच्छित समय पर हमला करते हैं और सुरक्षा बलों को भारी क्षति पहुँचाते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या में गिरावट का आना उसके खिलाफ चल रही मुहिम की सफलता को मापने का एक भ्रामक संकेत है क्योंकि जिन क्षेत्रों में उनकी कार्यवाही पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही है वहां इस तरह की आतंकवादी हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर वे नागरिकों के बीच उत्तेजना नहीं फैलाना चाहते ताकि उन इलाकों में अधिक सुरक्षा बलों का ध्यान आकर्षित न हो।
- जेहादी आतंकवाद का मुकाबला करने में विफलताः 2005 के बाद जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर के बाहर कम से कम 25 बड़े आतंकी हमलों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3,000 से अधिक घायल हो गए। इन हमलों के पीछे या तो सीधे लश्कर–ए–तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का हाथ था अथवा यह इन दोनों आतंकी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए थे। कुछ कार्यकर्ताओं और महत्वपूर्ण नेताओं के निराकरण के बावजूद आईएम (जिसका नेतृत्व पाकिस्तान में स्थित है) और लश्कर की कई स्वतंत्र सेल देश में मौजूद हैं तथा पाकिस्तान देश में ऐसे और अधिक सेल शुरू करने और भारत पर हमलों को निष्पादित करने की क्षमता

रखता है। इसका कारण यह है कि यह आतंकी ढांचा पाकिस्तान में मजबूती के साथ बरकरार है और जिहादियों को भारत भर में कुछ इलाकों में स्थानीय समर्थन और संरक्षण लगातार प्राप्त हो रहा है।

- आतंकवाद विशेषरूप से जेहादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वोट बैंक राजनीति सबसे बड़ी बाधा है। इससे सुरक्षा बलों का पूरा मनोबल गिरता है। इसका सबसे विभत्स रूप श्री नरेन्द्र मोदी के अक्टूबर 2013 की पटना की हुँकार रैली में देखने को मिला जिसमें बिहार सरकार ने जेहादी आतंकवादी हमलें को रोकने में कोई सक्रियता नही दिखाई। हम बिहार की जनता का अभिनन्दन करना चाहते है कि बम हमलों में बड़ी संख्या में घायल और मरने के बावजूद उन्होंने संयम का परिचय दिया। जब बटला हाउस के आतंकवादी हमलें में एक बहादुर पुलिस पदाधिकारी मरता है और वही कॉंग्रेसी नेता आतंकवादियों के पक्ष में बयान देते है तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है।

- सरकार संगठित होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र (एनसीटीसी) के रूप में एक केंद्रीकृत संस्था की स्थापना के लिए देश में राजनीतिक आम सहमति कायम करने में असमर्थ रही है। चूंकि जिहादी आतंकवाद बहुस्तरीय है जो जटिल वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, अतः उस पर नजर रखने और उसे कुचलने के लिए राज्य सरकारों के पास खुफिया क्षमताओं और संसाधनों की कमी है जिसके कारण इससे निपटना व्यक्तिगत स्तर पर राज्य सरकारों के बूते के बाहर है। हालांकि आतंकवाद का सामना करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की थी और एक गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम भी पेश किया था, यह मात्र प्रतिक्रियाशील उपाय जो आतंकी हमलों को रोकने में बेहद सीमित भूमिका अदा करते हैं। आतंकवादी संगठनों के बारे में खुफिया सूचनाओं की साझेदारी और एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना के लिए प्रारंभ की गई NATGRID परियोजना में भी अभी तक कुछ अधिक प्रगति देखने को नहीं मिली है। हालांकि आतंकवाद से निपटने के लिए देश के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, फिर भी यूपीए सरकार इस संबंध में राज्यों से पर्याप्त परामर्श व संवाद स्थापित करने में विफल रही।

- राजग सरकार द्वारा शुरू की गई बहु–उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (MNIC) परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा एक राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना था जो कि गैर भारतीय नागरिकों की पहचान को आसान बनाता व आतंकवाद से और प्रभावी रूप से लड़ने में मदद करता, लेकिन यूपीए सरकार ने पूरी परियोजना को उद्देश्य से भटकाते हुए राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए दो समानांतर परियोजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया जिनमें गृह मंत्रालय और यूनिक आइडेंटिफिकेशन (यूआईडी) या आधार योजना शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार के समाज कल्याण के वितरण का सुनिश्चित करना था. शुरुआत में जहां इन दोनों परियोजनाओं के लगभग समान उद्देश्य थे, आगे चलकर इनके मध्य हितों का टकराव व वित्तीय संसाधनों को लेकर संघर्ष होने लगा, जिससे इनके संचालन के समय में देरी और लागत में वृद्धि होती चली गई।

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। केंद्र सरकार ने पहले आतंकवाद निरोधक कानून (पोटा) को समाप्त कर दिया जोकि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत कानून था। उसी तरह इसने गुजरात के आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (GUJCOCA) को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जबकि एक पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मकोका में इसी तरह के प्रावधान हैं। संप्रग सरकार ने बार–बार आतंकवाद के संरक्षकों को संकेत दिया कि उनके खिलाफ की गई कोई भी प्रभावी कार्रवाई उसके अपने वोट बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

- सरकार ने खुफिया एजेंसियों में संख्याबल की कमी को रेखांकित करने और उनकी तकनीकी क्षमता के उन्नयन की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। इसने विभिन्न एजेंसियों को एक–दूसरे के खिलाफ खड़ा करके

उनके कर्मियों का मनोबल गिराया है और राज्य संस्थाओं को भीषण रूप से कमजोर किया है। उदाहरण के तौर पर एक कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ के मामले में आईबी के अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया।

सरकार को एहसास होना चाहिए कि जो संस्थाएं आतंकवाद से मुकाबला करने में आखिरी स्तम्भ रही हैं उन्हें ही जांच के दायरे में डालना राष्ट्र की सुरक्षा को कितने बड़े खतरे में डालने के बराबर है।

- कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर बर्बर पुलिस कार्रवाई' के शिकार के रूप में चित्रित कर के पूरी बहस का सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश कर रही है। हालाकि निर्दोष व्यक्तियों की गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है, फिर भी आतंकवाद के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई को जानबूझ कर मुसलमानों के खिलाफ लक्षित प्रताड़ना के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और इसका सांप्रदायिक मकसद हैं। दूसरी ओर, कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, एक आतंकवादी संगठन के रूप में आईएम की पहचान करने से साफ इंकार करते है। उन्हें यह एहसास होना चाहिए की इंडियन मुजाहिदीन (प्रतिबंधित) को एक आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकार करना एक पूरे समुदाय को आतंकवादी नाम देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता एक बार फिर उजागर हुई जब राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक भाषण में दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश में दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने के लिए उनके साथ संपर्क में थी।
- सरकार विदेशों से धार्मिक दान और धन हस्तांतरण के नाम पर आतंकवादियों को किए जा रहे धन के प्रवाह का पता लगाने और इस पर रोकथाम लगाने में नाकाम रही है। खाड़ी देशों से दाताओं द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे वहाबी मदरसों की एक बड़ी संख्या की वैधता और इरादों का पता लगाने में इस सरकार की असमर्थता से भारत के दुश्मनों को देश में अपना जाल फैलाने में काफी मदद मिली है। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में चल रहे ऐसे कई मदरसे विशेष रूप से इस आतंकी हमलों में मदद करने में शामिल रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार उनकी गतिविधियों और धन के स्रोतों की जांच करने में नाकाम रही है, भले ही भारत में रहने वाले मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद वहाबी विचारधारा का विरोध करती है जो इस भूमि के लिए विदेशी है।
- आतंकी हमलों के लगातार खतरे ने राष्ट्र के नागरिकों के बीच चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। इसके अतिरिक्त सरकार की निष्क्रियता और पाकिस्तान जोकि भारत के खिलाफ निर्देशित आतंकवाद का केंद्र है, के प्रति नरम रुख ने भी देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार के संकल्प को लेकर उनके मन में अविश्वास को बढ़ा दिया है। आतंकवाद की लगातार घटनाएं देश की सुरक्षा के माहौल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती हैं और देश के आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं।

विफलता

विदेश नीति की

5.0 विदेश नीति की विफलता

- पड़ोसी देशों के साथ भारत के राजनैतिक रसूख में गिरावट आई है। कांग्रेस ने वादा किया था कि वह परम्पराओं पर आधारित बुद्धिमत्ता पूर्ण विदेश नीति का निर्माण करेगी। लेकिन बीते 5 वर्षों के दौरान हमारी विदेश नीति में न तो आत्मविश्वास देखने को मिला, न ही पड़ोसी देशों से पैदा हो रहे खतरों के प्रति चिंता। हमारा एक पडोसी देश की चीन के साथ बढ़ रही घनिष्ठता चिंता पैदा करने वाली है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध की दशा हमारी विदेश नीति में गिरावट और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकने में हमारी असफलता को दर्शाते हैं।

- **पाकिस्तान :** पाकिस्तान के प्रति UPA की नीति बुरी तरह असफल रही है। पाकिस्तान के साथ वार्ताओं के दौर में आतंकवाद के मुद्दे को साइडलाइन कर देना हमारी चूक को दर्शाती है। ''भगवा आतंकवाद'' के काल्पनिक विचार का सृजन कर और इसे आगे बढाकर इस सरकार ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित वैश्विक आतंकवाद को देश में घटने वाली आतंकवाद की कुछ छिटपुट घटनाओं को एक समान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा हमारे खिलाफ जबरदस्ती प्रचारित जल संबंधी प्रचार को चुनौती देने में हम विफल रहे। पाकिस्तान हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए जेहादी समूहों और हाफिज सईद को लगातार राजनीतिक स्थान देने में कामयाब रहा।

  शर्मल शेख सम्मेलन में डा. मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि द्विपक्षीय वार्ता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के परिणामों से बाधित नही होगी और पाकिस्तान भी आतंकवाद का भुक्तभोगी है। यह सोच जनवरी 2004 के वाजपेयी–मुर्शरफ करार के बिल्कुल खिलाफ है जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार यह माना था कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ नही होने देगा। इस पूरी सोच से पाकिस्तान का उत्साह मुम्बई हमलों के अपराधियों के खिलाफ कारवाई नही करने की ओर बढ़ा है। लश्कर ए तैयबा और जमात उत दावा संगठनो को वहा की सेना और पंजाब सरकार का सीधा समर्थन मिलता है जिसके मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के छोटे भाई है। इसी कारण हमने पाकिस्तान प्रायोजित काबुल में भारतीय दूतावास और जलालाबाद के काउन्सलिट के हमलों पर गंभीर उदासीनता बरती।

- **अफगानिस्तान :** सैन्य उपकरणों और हथियारों के लिए अफगान सरकार की मांगों के प्रति भारत भारत का रवैया उदासीन रहा, अगर भारत ऐसा करता तो अफगानिस्तान के सैनिकों को तालिबान से मुकाबला करने में मदद मिलती क्योंकि 2014 के बाद वहां से विदेशी सैनिक वापस चले जायेंगे।

- **नेपाल :** चीन ने नेपाल में स्थिर पैठ बना ली है। चीन वहां कई बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गलियारे बनाने की परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। नेपाल ने भारत के साथ आधी सदी से ज्यादा नेपाल मैत्री संधि और नदी जल बंटवारे की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बात कही है। चीन नेपाल के सेना पुलिस और को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, अभी तक इस काम के लिए नेपाल की निर्भरता भारत पर थी। यहाँ तक कि एक बार नेपाल ने भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती के लिए भी इनकार करने की बात कह दी थी। नेपाल और भारत के बीच परम्परागत ऐतिहासिक और धार्मिक सम्बन्ध है और लोगो के बीच काफी स्नेह है और हम सभी इसका सम्मान करते है लेकिन इन अनिश्चिताओं के कारण वह दवाब में है।

- **भूटान :** चीन भूटान के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना वहां अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करने में लगा हुआ है। जबकि भूटान अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों को लिए सदैव भारत पर निर्भर रहा है।

- **म्यांमार :** सरकार ने म्यांमार के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढाने और म्यांमार को चीन की छाया से मुक्त करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। चीन म्यांमार में सड़कों और हवाईअड्डों का निर्माण कर रहा है। चीन सितवे में एक गहरे समुद्रीय बंदरगाह का निर्माण कर रहा है जो और तेल और गैस पाइपलाइनों को चीन में कुनमिंग के साथ पोर्ट से कनेक्ट करेगा। भारत सरकार म्यांमार के साथ पूर्वी एशिया – सीमा पार आर्थिक और परिवहन गलियारे का निर्माण करने में भी विफल रही जिसकी वजह चीन पर म्यांमार की आर्थिक निर्भरता को कम किया जा सकता था। पूर्वोत्तर में कई घुसपैठिये संगठन म्यांमार की जमीन से अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर में सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है।

- **बंगलादेश :** भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बारे में चिंताओं के समाधान के बिना तीस्ता जल और भूमि सीमा मुद्दों का एकतरफा समाधान करने की कोशिश की। बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरता और भारत विरोधी भावनाओं को नकारात्मक रूप से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा। कट्टरपंथी तत्वों जमात ए इस्लामी के सत्ता में आने पर बांग्लादेश जिहादियों के लिए एक और लांच पैड बन जाएगा। चीन चटगांव के बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में विकास कार्यों में संलग्न है। चीन कॉक्स बाजार में एक हवाई अड्डे के निर्माण के साथ साथ Sonadia में एक गहरे समुद्रीय बंदरगाह के निर्माण की योजना बना रहा है।

- **श्रीलंका :** सत्ता में बने रहने और क्षेत्रीय राजनीति खोज की विवशता की वजह से भारत की सरकार को 2009 में लिट्टे के खिलाफ युद्ध के अंतिम चरण में श्रीलंका का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार 2009 में युद्ध के अंतिम चरण के दौरान लिट्टे और श्रीलंका के सशस्त्र बलों के बीच फंस गए निर्दोष तमिल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी विफल रही। भारत की चिन्ताओं से बेफिक्र श्रीलंका चीन से सामग्री और कूटनीतिक समर्थन लगातार प्राप्त करता रहा। युद्ध के बाद भी सुलह के प्रयासों में भारत श्रीलंका के तमिलों के लिए शक्तियों के वास्तविक हस्तांतरण सुनिश्चित करने में विफल रहा और श्रीलंका में चीन के प्रभाव को घटाने के लिए leverages का अभाव हो गया है साथ ही श्रीलंका को चीन के प्रभाव से मुक्त करवाने के प्रयास में भी असफल रहा।

- भारत और श्रीलंका के मध्य असहज हो रहे संबंधों का लाभ उठाते हुए चीन ने श्रीलंका के सशस्त्र बलों को सैन्य हार्डवेयर और गोला बारूद की आपूर्ति करके इस द्वीप राष्ट्र में पैर जमाने में सफलता प्राप्त की। चीन ने Hambantota में सामरिक समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जबकि इस बंदरगाह के निर्माण के लिए पहले प्रस्ताव भारत के लिए आया था। चीन कोलंबो में एक कंटेनर बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है। यह सभी परियोजनाएं तमिलनाडु के बहुत करीब स्थित हैं। चीन इसके माध्यम से हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी धमक कायम कर सकता है। तमिल पार्टियों के दवाब में आकर भारत के प्रधानमंत्री ने कोलम्बो में नवम्बर 2013 में आयोजित CHOGM सम्मलेन में भाग नहीं लिया जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के मध्य अविश्वास का खाई बढ़ गई, जिसकी वजह से भारत ने 2009 में वहां हुए युद्ध के के दौरान तमिल नागरिकों पर युद्ध अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंका पर दबाव डालने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे भारत और श्रीलंका के रक्षा संबंधों को चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं के श्रीलंकाई सशस्त्र बल (SLAF) के साथ उनकी में तेजी से बढ़ती नजदीकियों की वजह से धक्का लगा है।

- **मालदीव :** उदारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के निष्कासन और कट्टरपंथी मोहम्मद वाहिद हसन के नेतृत्व द्वारा सत्ता पर कब्जा भारत की अपने पड़ोस में गिरती राजनीतिक ताकत का एक और उदाहरण है। एक देश जो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है के द्वारा वहां बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए काम कर

रही भारत की कम्पनी का करार संपत कर देना चौंकाने वाला है। कट्टरपंथी वहाबी समूहों से बढ़ रही अस्थिरता और बयानों ने लश्कर जैसे जिहादी समूहों को वहां पैर जमाने का मौका दिया है जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

नोट : उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संप्रग सरकार की उदासीनता, कुव्यवस्था और अक्षमता के कारण अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों में गिरावट आई है और साख में कमी हुई है जिनसे हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं।

- **दक्षिण एशिया :** दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का पारंपरिक प्रभाव और सद्भावना का भाव घट रहा है क्योंकि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है ताकि भारत की भूमिका को सीमित किया जा सके। पड़ोसी देशों के साथ अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने में भारत की कूटनीति की विफलता ने भी भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और साख को बट्टा लगाया है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका को सीमित करने के लिए समुचित उपाय अपनाने में भात हमेशा पिछड़ा हुआ दिखाई दिया, और प्रतिक्रिया देने तक अक्सर विलम्ब हो जाया करता था। केंद्र में सहयोगी दलों को बनाए रखने के राजनीतिक स्वार्थों को राष्ट्रीय हितों में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ विदेश नीति के अनुपालन में तरजीह दी गई।
- **शेष विश्व :** डॉ. मनमोहन सिंह ने अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश की प्रशंसा से अपना कार्यकाल शुरू किया। वह ऐसे समय में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं जब अमरीका में भारत को अपमानित करने की तमाम घटनाएँ घट रही हैं। अमेरिका के साथ भारत के मजबूत संबंधों की गति को आगे बढ़ाने के प्रयासों में कमी आई है. वही अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कजाखस्तान के साथ नागरिक परमाणु समझौतों औपचारिकता के बावजूद भारत के पारंपरिक सहयोगी रूस के साथ संबंधों में स्थिरता आई है। सरकार परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन के लिए रिएक्टरों को परिचालित करने में नाकाम रही है। इस कारण न केवल इन देशों के साथ संबंधों का नुकसान ही नहीं हुआ है बल्कि देश में पहले से मौजूद उर्जा का संकट और बढ़ गया है। भारत की विदेश नीति की इस दिशा से हम पूर्वी एशियाई देशों विशेष रूप से जापान और वियतनाम के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, जिससे चीन का प्रभाव कम किया जा सकता था। भारत दक्षिण चीन समुद्र चीन से धमकी के बाद तेल अन्वेषणों के कार्य से भे पीछे हट गया। विश्व की कोई भी बड़ी शक्ति भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान द्वारा की जा रही पर मुखर नहीं हुई, जो कि भारत की भू राजनीति के कमजोर होने के संकेत हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों

के विकास के प्रति

उदासीन

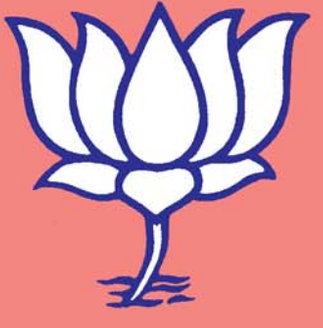

6. पूर्वोतर राज्यों के विकास की अनदेखीः

- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आसाम से कई वर्षों से राज्यसभा के सदस्य है, किन्तु पूर्वोतर राज्य विकास के मामले में भारी उपेक्षा के शिकार है। सिर्फ दिखावे के लिए वे कुछ बैठके करते है किन्तु सही विकास के मामले में प्रधानमंत्री और कांग्रेस दोनों ने पूर्वोतर राज्यों में गम्भीर उदासीनता दिखाई है।
- जुलाई 2012 में कोकराझाड़ में भारी संप्रदायिक दंगो के बाद लगभग 2.5 लाख लोग बेघर हो गये जिसका असर जम्मू कश्मीर और मुम्बई के आजाद मैदान की रैली में भी देख गया जहॉ शहीद स्मारक को क्षति पहुचाई गई। बंगलोर और अन्य स्थानों पर पूर्वोतर राज्य के छात्रों पर हमला भी करने की कोशिश की गयी। आजतक इस गम्भीर घटना के अभियुक्त नही पकड़े गये है।
- आसाम में पिछले दस वर्षो में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नही किया गया है।
- नागालैण्ड के लोगो को इस बात की बहुत पीड़ा है कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री ने एक बार भी नागालैण्ड जाने की जरूरत नही समझी।
- मेघालय विधानसभा का अपना भवन नही हैं।
- रैडक्लीफ लाइन की समस्या का निदान आज तक नही हो पाया है, जो मेघालय की खासी और गारो क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यह समस्या 1971 के बंग्लादेश बनने के समय के युद्ध से ही चली आ रही है।
- पूरे पूर्वोतर राज्यों में यह आम चर्चा रहती है कि बड़ी मात्रा में जन वितरण प्रणाली का चावल, किरासन तेल और मवेशी अर्न्ताराष्ट्रीय सीमा से गैर–कानूनी तरीके से बंग्लादेश में भेजे जाते है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही तो दूर, दिल्ली में इसकी चर्चा भी कम होती है।
- 15000 करोड़ विभिन्न सिंचाई की परियोजनाओं में लगाए जाने के दावे के वावजूद सिर्फ 5 प्रतिशत सिंचाई में बढ़ोतरी का आरोप है।
- 3000 मेगावाट के देश के सबसे बड़े दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट की आधार शिला प्रधानमंत्री ने फरवरी 2008 मे रखी किन्तु नवम्बर 2013 तक यह योजना विभिन्न स्वीकृतियों के अभाव में आरम्भ भी नही हो सकी। समाचार पत्रों मे यह बात बार–बार छपती है की 11000 मेगावाट के लगभग 25 प्रोजेक्ट जो अरूणाचल प्रदेश को पिछले एक दशक में दिए गए उनमें एक पर भी कार्य आरम्भ नही हुआ है।
- अरूणाचल के दिबांग घाटी के दामबेंग सेक्टर में एडवांस लैण्डिंग साइट एक जंगल के रूप में प्रतीत होता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है और अरूणाचल प्रदेश का चीन की सीमा से लगे होने के कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है, फिर भी संप्रग सरकार का इस ओर कोई ध्यान नही गया है।
- 2007 में 24000 करोड़ के पीएम पैकेज के साथ ट्रांस अरूणाचल हाइवे के निर्माण की घोषणा की गई थी जो 7 साल के बाद अभी आरम्भ भी नही हुई है।
- इस बात की बहुत गम्भीर आशंका है कि नागरिको के बनने वाले राष्ट्रीय रजिस्टर में मेमंग सिंह और आसाम के मुसलमानों के बीच के अंतर की अनदेखी की जा रही है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है क्योंकि यह नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है।
- एक सिंग वाला गैंडा आसाम का एक गौरवशाली प्रतीक है जिसकी सुरक्षा की पूरी अनदेखी हो रही है। पिछले एक वर्षो में 258 गैंडों की हत्या हुई है अथवा उनके सिंग काटे गए है। ब्रह्मपुत्र वैली में इनके स्वभाविक निवास वाले जंगल के क्षेत्रों में आजकल अवैध घुसपैठियों का अतिक्रमण हो रहा है।
- 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नें डिब्रूगढ़ के नजदीक बोगीबिल रेलमार्ग को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया था जिस पर आज तक कोई प्रगति नही हुई।
- राष्ट्रीय राजमार्ग का ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर भी पूर्वोतर क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति में है, जिसकी शुरूआत राजग सरकार के समय की गयी थी।
- ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी है फिर भी इस पर मात्र तीन पुल है जबकि अन्य कई की आवश्यकता है।
- आसाम में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है जिसमें भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता है, फिर भी केन्द्र सरकार के द्वारा कोई निर्देष तक नही दिया गया कार्यवाही की बात तो दूर, क्योंकि आसाम में कॉग्रेस की सरकार है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

7.0 शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- IIT संस्थानों में 40% प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय संस्थानों में यह प्रतिशत 30% पद एवं प्ड में 25% है।
- डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से 150 तक पहुँच गई है, यह विश्वविद्यालय नियमों और मानकों के उल्लंघन करके स्थापित हो रहे हैं।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय में महानिदेशक के पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं।
- चिकित्सा परिषद् जो कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करती है, उसके मुखिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है।

- **स्वास्थ्य सेवायें**
  - UPA 2 सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवायें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 फरवरी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरक पर पिछले 10 सालों में दी जाने वाली पांच गुना बढ़ गई, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षित रहा। इस वर्ष के बजट में वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बजट में 20.6 प्रतिशत की कटौती की है।

अवमूल्यन

संस्थाओ की गरिमा का

8.0 संस्थानों को कमजोर करना

- कॉंग्रेस नेतृत्व की संप्रग सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की गरिमा, निष्ठा और विश्वसनीयता को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। विशेष रूप से वे संस्थाए जिनका दायित्व सरकार के आचरण और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है, सरकार के योजनाबद्ध हमले की शिकार रही है क्योंकि सरकार नही चाहती कि वे सरकार की गड़बडिघ्यों को उजागर करें। सरकार ने ये भी कोशिश की इन संस्थाओं मनचाही नियुक्तिया की जाए।

- सीएजी के ऊपर प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के द्वारा हमले किए गए, आलोचना कि गयी और उनके सवैंधानिक दायित्व पर ही सवाल उठाए गए क्योंकि सीएजी ने विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर, तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था।

- जिस प्रकार से सीवीसी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर सरकार ने विपक्ष की नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की आपत्तियों को दरकिनार कर श्री पी.जे. थॉमस जैसे कई सवालों से घिरे पदाधिकारी की नियुक्ति का दबाव बनाया उससे इस महत्वपूर्ण संस्था की गरिमा पर ठेस लगी। बाद में सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस नियुक्ति को ही रद्द कर दिया।

- सीबीआई के दुरूपयोग में कॉंग्रेस के सरकार ने सभी मर्यादाओं को तार–तार कर दिया है। प्रधानमंत्री समेत कॉंग्रेस के मंत्री और सहयोगी दलों के नेताओं को बचाने के लिए दबाव और विपक्ष को फँसाने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग एक आम बात हो गयी है।

- जे.पी.सी. ऐसी महत्वपूर्ण संसदीय संस्थाओं का भी खुलकर दुरूपयोग करने की कोशिश की गई। आजाद भारत के एक सबसे शर्मनाक घोटाले 2जी की जाँच के लिए बनाई गयी जे.पी.सी. के अध्यक्ष ने कॉंग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अधिक काम किया। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री, वितमंत्री और सरकार को क्लीनचिट दी और संसदीय मर्यादाओं का खुला उल्लंधन किया।

- संसद की दूसरी प्रमुख संस्था पब्लिक एकाउंटस कमिटी (पी.ए.सी.) को भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जाँच से रोकने के लिए सरकार ने हर षड्यंत्र का इस्तेमाल किया।

- सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने चुनाव आयोग के निर्णयों की भी सार्वजनिक रूप से आलोचना की है।

- भारत का सविंधान संघीय सिद्धांतो की महत्वपूर्ण अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने संघीय ढाँचे की पूरी बुनियाद पर ही प्रहार किया जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा चलायी जाने वाले राज्य में हर प्रकार के अवरोध, षड्यंत्र और केन्द्र सरकार की शक्तियों का खुला दुरूपयोग तक किया गया।

वादा खिलाफी

2009 कांग्रेस घोषणापत्र

को पूरा नही करना

9.0 आरोपों का आधार कांग्रेस का 2009 का घोषणा पत्र और उसमें किये गए वादों को पूरा करने में विफलता पर आधारित है। (कांग्रेस घोषणापत्र के क्रमानुसार सूचीबद्ध)

कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए गंभीर वादे किये। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसका जिक्र "The Work Programme: 2009–2014". के शीर्षक के साथ किया गया है। इस प्रकार के कुल 29 वादे किये गए थे, जिनमें से अधिकतम अधूरे ही रह गए।

9.1 सबसे पहले कहा जाता है "हम देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकतम संभव सुरक्षा की गारंटी देंगे। आतंकवाद चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमारी नीति आतंवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रहेगी। विशेष बटालियनों की अधिक संख्या में स्थापना की जायेगी और देश भर के महत्वपूर्ण ठिकानों पर उनकी स्थापना की जायेगी"।

- UPA सरकार पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों को संदेह का लाभ देती रही। पाकिस्तान से उसकी भूमि द्वारा चलाये जा रहे आतंकवाद को बंद करने की गारंटी लिए बिना उसके साथ बातचीत करती रही। इसके उलट UPA सरकार ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ सर क्रीक, सियाचिन और जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर सचिव स्तर की कई दौर की वार्ता की। इस बातचीत के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सामने 26/11 के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शर्त भी नहीं रखी।

- कांग्रेस कारगिल युद्ध, कंधार अपहरण और ऑपरेशन पराक्रम को हमारी "मजबूत" नीति की असफलता के तौर पर गिनाती है। कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम को विफल बताकर कांग्रेस जंगी कारवाई में देश की जवानों की सर्वोच्च शहादत का अपमान कर रही है। देश के की जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रति लचर और घुटनाटेक नीति के कारण सीमा पार आतंक पर हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने में असफल रहे। डॉ. मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के बातचीत करने की उत्सुकता का नतीजा शर्म–अल–शेख–2009 में राजनयिक आपदा के रूप में सामने आया। (डॉ. मनमोहन सिंह पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से 26/11 के हमले के बाद 8 बार मुलाकात की)। इस दौरान 26/11 का मुख्य आरोपी हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा एवं जेल में बंद लश्कर के अन्य आतंकी जकी उर रहमान, रहमान लखवी, युसूफ मुज्जमिल की आवभगत की जाती रही, जो कि जेल से ही अपनी गतिविधियाँ चला रहे थे। पाकिस्तान की जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों जमात उद दवा और लश्कर–ए–तैयबा के आतंकी कैम्पों और वहां की पंजाब सरकार द्वारा इनको आर्थिक मदद देने के विषय में भारत को अहम् सबूत मिलने के बावजूद भी भारत इसको पाकिस्तान के सामने ठीक ढंग से पेश नहीं कर सका, न ही पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दवाब बना सका।

- 26/11 के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर पर्याप्त राजनयिक और सैन्य दवाब न बना पाना UPA की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। UPA सरकार पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्यवाही की प्रतिबद्धता लिए बिना केवल बातचीत करने के लिए उत्सुक दिखी। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा, कश्मीर मसले के हल के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने की मांग करता रहा, हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आतंकवाद का आरोप भारत के सर पर मढ़ दिया। पाकिस्तान ने भारत को अभी व्यापार प्रयोजन के लिए पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। जबकि भारत पाकिस्तान को यह दर्जा दे चुका है। सरकार आतंकवाद की समाप्ति तक पाकिस्तान के साथ वार्ता न करने के अपने वचन में विफल रही है। सरकार की लचर और सुस्त विदेश नीति के करण पाकिस्तान ने हमारे देश आतंकी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है, ताकि वह अपनी शर्तों पर द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने का दवाब बना सके। 26/11 के हमले की भारी कीमत इस देश को चुकानी

पड़ी है, बजाय इसके कि सरकार इस हमले में पीड़ित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करती, सरकार हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में नजर आई। सरकार भारत के पक्ष में सिंधु जल के बंटवारे पर विश्व बैंक के फैसले को भुनाने करने में विफल रही। झेलम के पानी का 60% से भी अधिक भारत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उपरोक्त विषय में वर्ल्ड बैंक द्वारा हमारे पक्ष में दिया गया निर्णय पाकिस्तान के ऊपर आतंक पर लगाम लगाने के सन्दर्भ में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था।

- पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंक की घटनाएँ लगातार जारी हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। 2012 के बाद से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ की घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं। सीमा पर भारतीय जवानों की हत्या और उनके सर काट लेने जैसी घटनाओं के बाद भी मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से न्यूयॉर्क में भेंट की। जब यह मुलाकात हो रही थी उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों कश्मीर में हीरानगर और साम्बा में हमला किया। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंक की घटनाएँ लगातार जारी हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। 2012 के बाद से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ की घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं।
- वर्ष 2009 से दिसम्बर 2013 तक भारत के ऊपर 21 कम और उच्च क्षमता वाले आतंकी हमले हुए। इन हमलों में सौ से अधिक लोगों की जाने गईं और हजारों लोग घायल हुए। आतंकी हमलों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आई है।
- राणा और हेडली की महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति और गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान को कई डोजियर सौंपने के बाद भी भारत मुंबई हमलों के दोषियों को खिलाफ कार्यवाही करवाने में असफल रहा।
- तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए जो ढांचा खड़ा करने का वादा किया गया था, वह बनने से पहले ही ध्वस्त हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा "zero tolerance' का दावा हास्यास्पद प्रतीत होता है।

9.2 "विशेषज्ञ बटालियनों की स्थापना और उनकी महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्ति," कांग्रेस घोषणा पत्र का वादा।

पूर्वोत्तर सीमाओं के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना के सन्दर्भ में सरकार सही ढंग से खतरा के गंभीरता का आकलन अभी तक नहीं कर सकी है। सरकार का उदासीन रवैया और सामरिक दृष्टि में कमी वित्त मंत्रालय द्वारा इस विषय में 2011 में दर्ज की गई उस आपत्ति से जाहिर होता है जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या चीन हमारे देश के खिलाफ कभी युद्ध करेगा? देश को चीन से खतरा है, यह तथ्य जानने के लिए UPA सरकार को 8 साल लग गए और स्ट्राइक कोर की मंजूरी पत्र नवंबर 2013 में जारी किया गया।

9.3 कांग्रेस घोषणा पत्र के पहले वादे के तौर पर आधार कार्ड का भी जिक्र किया गया है।

"हमारे देश में उपलब्ध बड़ी आईटी विशेषज्ञता के साथ प्रत्येक भारतीय को आधार पहचान पत्र उपलब्ध करवानावह भी 2011 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के प्रकशन होने के बाद"।

- सरकार खोखला वादा करती रही कि आधार पहचान पत्र के लिए (UIDAI) की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी आदेश 2009 के अंतर्गत हुई है और यह योजना आयोग साथ संलग्न है। जबकि संसद के किसी भी अधिनियम द्वारा इस महंगी और संवेदनशील कवायद का समर्थन नहीं किया गया है।
- UIDAI के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत कुल Rs 12,398 करोड़ के बजट में 31 जुलाई 2013 Rs 3,062 करोड़ खर्च किये गए थे। योजना आयोग राज्य मंत्री का राज्य सभा में दिया गया लिखित में जवाब।

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-08-29/news/41582259_1_uid-project-uid-number-enrolment

- यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किये आधार पहचान पत्र नियमित आधार पर जारी किये जा रहे हैं, जबकि तमाम राजनैतिक दल, मीडिया और यहाँ तक कि अदालतें भी इसकी स्वीकार्यता और व्यवहारिकता पर सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह पहचान पत्र वास्तविक नागरिक के जो नागरिक अधिकार हैं उसके ऊपर है? यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है जिस पर आखिरी फैसला आना बाकी है।
- मीडिया में यह रिपोर्ट किया गया कि बड़ी मात्रा में आधार कार्ड कूड़े के ढेर में पाए गए साथ ही बड़ी तादाद में ऐसे आधार कार्ड भी मिले हैं, जिनमें फोटो लगाने का स्थान रिक्त है।
- इन कार्ड के लिए जुटाया जा रहा बायोमेट्रिक डाटा जिसे कि भारत सरकार के आधिपत्य में होना चाहिए वह डाटा कथित रूप से विदेशी एजेंसियों के पास है जिससे इस देश के नागरिक की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। जिस प्रकार से यह योजना चलाई जा रही है, उसके कारण कोई भी सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है बल्कि कुछ अन्य मुद्दे और समस्याएं खडी हो गई हैं।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) भारत के राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर को डिजिटल बायोमेट्रिक बनाने के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। UIDAI अब तक निर्धारित 60 करोड़ में से 56 करोड़ आधार कार्ड जारी कर चुका है. वहीँ 14 करोड़ लोगों को RGI द्वारा राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर में नामांकित किया गया है। The Economic Times की खबर के अनुसार", "जनवरी 2012 तय की गई एक व्यवस्था के अनुसार 60 करोड़ पहचान पत्र UIDAI जारी करेगा और बचे हुए 60 करोड़ RGI द्वारा बनाये जायेंगे। 2011 में एनपीआर प्रकाशित करने के वायदे को पूरा नहीं किया गया।

  http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/29551493.cms\utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

9.4 कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक और अन्य महत्वपूर्ण वादा किया गया था कि "हम रक्षा तैयारियों के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी बेहतर प्रयास करेंगे। पिछले 5 वर्षों में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के कार्य की बहाली को बेहतर प्रकार से किया गया है। इसमें और तेजी लायी जायेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह प्रण है कि भारत के सैन्य बलों को आधुनिक तकनीक, हथियारों, जलपोतों और विमानों से लेस किया जाएगा ताकि वे जल, थल और नभ में किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकें"।

Recognizing their special concerns, a new and separate department of ex-servicemen's welfare was established in 2004 by the Congress-led UPA Government- Ex-servicemen constitute a large cadre of dedicated and trained persons. **We will utilize them extensively in crucial nation-building tasks."**

- इस विषय की गंभीरता को समझते हुए भाजपा केवल उन्हीं मुद्दों की चर्चा करना चाहती है जो पहले से ही सार्वजनिक हैं।
- रक्षा खरीद में नियमित देरी, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की वजह से देश की रक्षा तैयारियों को झटका लगा है। अगस्ता वेस्टलैंड से हेलीकाप्टर खरीदी और Tatra ट्रक खरीदी में बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के हालिया

उदाहरण हमारे सामने है। यह समस्या रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाली फर्मों को बड़े पैमाने पर ब्लैक लिस्ट करने के कारण पैदा हुई, परिणामस्वरुप ऐसे हालात निर्मित हो गए हैं कि हमारे पास रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कम्पनियां उपलब्ध नहीं है। इन कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने से भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है बल्कि देरी की वजह से रक्षा खरीद में भारी इजाफा हुआ है। तीनों सेनाएं निम्नलिखित उपकरणों की भारी कमी से जूझ रही हैं, ऐसे में अगर देश को किसी संभावित युद्ध का सामना करना पड़ जाए तो देश को भयावह संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उनकी विशेष चिंताओं को समझते हुए UPA सरकार ने 2004 में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक नए और अलग विभाग की स्थापना की। पूर्व सैनिक समर्पित और प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक बड़ा संगठन है। हम राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी बेहतर भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

तोपें: 1984 में भारत द्वारा स्वीडन से 400 बोफोर्स तोपें खरीदी गई थीं, यह तोपों की आखिरी सबसे बड़ी खरीद थी। स्वचालित बंदूकें, 155 mm की गन और पहाड़ों पर प्रयुक्त की जाने वाली विशेष बंदूकों की खरीदी का प्रस्ताव पिछले एक दशक के दौरान कई निविदाएँ जारी होने के बाद आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाया। तोपों की कमी भारत की रक्षा तैयारियों के मद्देनजर एक भारी खामी और चूक है।

- **हथियार :** सेना प्रमुख द्वारा 12.3.2012 को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि आर्मी के सभी टैंक बेड़े दुश्मन के टैंक को हराने के लिए ''महत्वपूर्ण गोला बारूद से रहित है"। उन्होंने आगे कहा कि सेना के पास "Large scale voids in" महत्वपूर्ण निगरानी और रात में लड़ने की क्षमता तंत्र का भारी अभाव है विशेषकर mechanised forces में। अँधेरे में लड़ने की क्षमता का अभाव, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से संघर्ष के समय भारत एक कमजोर पक्ष साबित हो कर रह जाएगा।

- **सेना वायु रक्षा :** भारत आज भी एंटी एयरक्राट गन सिस्टम L-70 (40 millimetre AD Gun System) and Schilka (ZSU-23-4 Schilka SP) और जमीन से हवा में मार करने के लिए Air Missiles जैसे SAM-6 और OSA AK का प्रयोग कर रहा है। एयर डिफेन्स में खामियों का जिक्र करते हुए सेना प्रमुख ने अपने पत्र में लिखा कि 90 प्रतिशत उपलब्ध हथियार प्रचलन में नहीं है और हमको विश्वास दिलाने में असमर्थ हैं कि यह हमें सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।

- **Infantry:** भारत के सामने मौजूद सुरक्षा खतरों के प्रकृति जिसमें मध्यम दर्जे के संघर्ष भी शामिल हैं, इन्फैंट्री भारतीय सेना की निर्णायक लड़ाई जीतने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हालाँकि भविष्य का Infantry Soldier विकसित करने के लिए (F-INSAS) परियोजना की परिकल्पना वर्षों पूर्व के गई थी। इन्फैंट्री में अभी भी आधुनिक संचार, निगरानी उपकरण, और मजबूत स्वचालित राइफलों का अभाव है। हमारी इन्फेंट्री दोषपूर्ण हैण्ड ग्रेनेड और मोर्टार के गोले में दुर्घटना की गंभीर समस्या से जूझ रही है। आधुनिक राइफल 7.62/9 mm calibre की खरीदी के लिए टेंडर जारी किये गए हैं।

- **Army Aviation:** पिछले कुछ वर्षों के दौरान सैनिकों और संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ सड़क के रास्ते नहीं पहुंचा जा सकता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में विमान के जरिये पहुँचाने में सेना की भूमिका बढ़ी है। परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हालाँकि मध्यम और भारी क्षमता वाले हेलीकाप्टर जैसे ध्रुव और चिनूक की खरीद के टेंडर जारी किये गए हैं, लेकिन प्रक्रियागत डेरी की वजह से अभी तक यह नहीं हो सका है।

- **नौसेना :** पनडुब्बियों और नौसेना के डाकयार्ड में लगातार हो रही दुर्घटनाओं से देश हैरान है। नौसेना प्रमुख

ने नौसेना के सम्मान की खातिर इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन सरकार और उसके मंत्री ने इन घटनाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। नौसेना की दुर्गति करवाने के बाद भी रक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहे।

- लगातार देरी और लागत में वृद्धि के बाद विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य जनवरी 2014 को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। भारत के पास जो पन्दुब्बियाँ हैं, वह पुरानी होती जा रही हैं। वर्तमान में केवल 7 पन्दुब्बियाँ हैं जो परिचालन में हैं। आगामी दशक में भारत को हिन्द महासागर में अपनी शक्ति को बढाने के लिए नौसेना को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लेस करना होगा, हालाँकि यह सरकार अभी तक ऐसा करने में असफल रही है।
- **वायु सेना :** भारतीय वायु सेना तेजी से चीनी और पाकिस्तानी वायु सेना पर अपनी गुणात्मक और मात्रात्मक धार खो रही है। MMRCA प्रोजेक्ट में विलम्ब के कारण अगले 5 वर्ष का समय और लगेगा वायुसेना को विमान हासिल करने के लिए। अनिर्णय और दोषपूर्ण खरीद की प्रक्रिया, कीमतों पर विक्रेता के साथ लम्बी बातचीत के कारण एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जब हमारे पायलट की ट्रेनिंग के जेट ट्रेनर भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह सब उस वक्त में हो रहा है जब वायु सेना नए लड़ाकू जहाजों, परिवहन विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए भारी संख्या में प्रशिक्षित पायलट की जरूरत होगी। वायु सेना के अंत में प्रशिक्षक विमानों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए आपातकालीन खरीद के लिए जाना पड़ा।
- रक्षा हार्डवेयर और संचार प्रणालियों में चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित घटकों की उपस्थिति एक प्रमुख सुरक्षा चिंता का विषय है। जिस पर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा तीनों सेवाओं के 21 वीं सदी युद्ध के मैदान में नेटवर्क पर बढ़ती निर्भरता के लिए C412SR सिस्टम के मद्देनजर प्रमुख उन्नयन की जरूरत है।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन : सरकार स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास और निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास में प्रोत्साहित करने नाकाम रही है हल्के लड़ाकू विमान (तेजस), मुख्य युद्धक टैंक (अर्जुन) परियोजनाओं को फिर से बहाल करने के लिए सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई है, जबकि इसके लिए कई दशक पहले खाका तैयार किया गया था। भारत अभी भी अपनी रक्षा उपकरणों के 70% आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है जिसके कारण कीमतों में वृद्धि की मार झेलनी पड़ती है और युद्ध के निर्णायक समय पर आपूर्तिकर्ता देश द्वारा स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में कटौती कर देने जैसे खतरे की सम्भावना भी बनी रहती है। सरकार को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए ताकि ड्रोन, रडार, निगरानी और संचार उपकरण, हथियार प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर आदि का निर्माण किया जा सके, जो कि युद्ध की विषम स्थितियों में प्रयोग में लाये जाते हैं।
- रक्षा खरीद के लिए हमारे देश में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें तमाम व्यवस्थागत खामियां हैं। रक्षा खरीद में अधिक समय का लगना, नौकरशाही उदासीनता की वजह से हमारी रक्षा तैयारियों में रिक्तता पैदा होती जा रही है। सोवियत युग के समस्त रक्षा उपकरणों को अब बदलने का समय आ गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में खरीद के लिए प्रस्तावित 250 प्रकार के उपकरणों में से मात्र 95 प्रकार के उपकरण की खरीद ही की जा सकी। चौंकाने वाला तथ्य है कि रक्षा मंत्रालय रक्षा मद में निर्धारित खर्च को बिना इस्तेमाल किये वापस कर रहा है। जबकि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि रक्षा आधुनिकीकरण तीव्र गति से जारी रहेगा।" सरकार ने भारत और चीन के मध्य सैन्य क्षमता के दृष्टिगत बढ़ते जा रहे अंतर को गंभीरता से नहीं लिया है। भारत

रक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत भी खर्च खर्च नहीं कर पा रहा है जो कि चीन जैसे देश से मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है।

- सरकार द्वारा सैन्य बलों के मनोबल को गिराकर भी रक्षा तैयारियों को कमजोर किया है। सेवारत सैनिकों के मन में यह व्यापक धारणा है कि सरकार सेवानिवृत सैनिकों को वन रैंक–वन पेंशन, सेवानिवृति के बाद रोजगार देने जैसे विषयों में न्याय नहीं करती है। आखिर वे कब तक और कितना इन्तजार करें न्याय के लिए। सैनिकों को विकलांगता पेंशन के खिलाफ सेना सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर कर देती है, जिसे सैनिकों के मध्य इस प्रकार का सन्देश के गया कि सेना प्रतिष्ठान अपने ही सैनिकों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से सेवारत सैनिकों का मनोबल कमजोर होता है, क्योंकि सेवा से हटने के बाद भी इनके संवर्ग का आपस में जुडाव रहता है। सेना से हर साल 50,000 सैनिक रिटायर होते हैं। सशस्त्र बलों में लगभग 13,000 अधिकारियों की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए और प्रतिभावान युवकों को सेना की तरफ आकर्षित करने के लिए भी सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रयास नहीं किये गए हैं। सेना में अधिकारियों की कमी होना गंभीर मसला है।
- रक्षा तैयारियों में कमी और खामियों को लेकर कई विशेषज्ञों ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी आवाज उठाई है। कम तैयारी अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन खुले में इस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ हैं। सरकार और सशस्त्र बलों के बीच जो अविश्वास का माहौल है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसका हमारे सेना के मनोबल पर विपरीत असल पड़ेगा, रक्षा तैयारियों के राह में यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

9.5 "हम उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे," कांग्रेस ने अपने 2009 के घोषणा पत्र में कहा था और साथ में यह भी कि "हम एक ऐसी योजना लेकर आयेंगे जिससे गरीब परिवारों को सस्ती दर पर बिजली मिल सके"।

- वादाखिलाफी करके कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। ये सरकार जनता को सस्ती दरों पर बिजली दे पाने में असफल रही। मई 2004 जब NDA सरकार बाहर हुई थी तब Rs 244 की दर से पर्याप्त मात्र में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध थे। UPA सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के दाम तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गए आज गैस सिलेंडर की कीमत Rs 845/– है। दरअसल UPA सरकार ने सिलेंडर की संख्या को वार्षिक आधार पर सीमित करके इसे गरीब और जरूरतमंद की पहुच से दूर बनाया है।
- हिंदुस्तान टाइम्स में 5.12.2013 को CAG के आंकड़ों के हवाले से छपी खबर के अनुसार 18632 MW की क्षमता वाले 55 पॉवर प्लांट इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि उनको प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नहीं हो हो पा रही है।
- गुटका बनाने और रियल एस्टेट का काम करने वालों को कोल ब्लॉक का आवंटन करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि देश को उर्जा सुरक्षा देने के लिए वह कितनी प्रतिबद्ध है। दिल्ली और देश के एक बहुत बड़े हिस्से का दिसम्बर 2012 में अँधेरे में डूब जाना कौन भूल सकता है।

9.6 कांग्रेस ने वादा किया था कि वे किसानों तथा उनके परिवारों की भलाई की लिए विभिन्न योजनाओं को विस्तार देंगे।

- दुर्भाग्य से किसानों की आत्महत्याएं देश भर में, तथा विशेष रूप से कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में अनवरत जारी रहीं। महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के किसान अपनी सरकारों के इस कष्टकारी रवैये से दुखी होकर खेती से विमुख होने को मजबूर हुए तथा उनका मामला संसद में सिर्फ भाजपा ने उठाया।

- स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए कारगर सुझावों को पूरी तरह से उपेक्षित कर विस्मृत कर दिया गया है।

9.7 कांग्रेस ने यह भी वचन भी दिया था कि खेती से जुड़ी सभी वस्तुओं तथा .षि उत्पादों के मुक्त आवाजाही को बाधित करने वाले सभी नियंत्रणों तथा किसानों की आय को सीमित करने वाले सभी नियमों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

- निर्यात नीति में निहित कई विसंगतियों ने कपास के किसानों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। कपास के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्ध के वक्त ने यह शक पैदा किया कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है, हालांकि कांग्रेस से इसका अपना घोषणापत्र याद रखने की उम्मीद बेमानी ही होगा।

9.8 कांग्रेस का एक और वादा यह भी था कि वे चयनित पंचायत संस्थाओं को वित्तीय रूप से सबल बनायेंगे।

- जम्मू कश्मीर जहाँ नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस सरकार चला रहे हैं, आतांकियों के कारण सरपंचों की जान खतरे में है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने इस पर मौन साधा हुआ है। वहां मुख्यमंत्री यह स्वीकार कर चुके हैं कि वह सभी सरपंचों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते। कांग्रेस और उसकी प्रतिज्ञा शायद, एक और दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं?

9.10 "कांग्रेस ने वादा किया था कि "हम वस्तु और सेवा कर अप्रैल 1, 2010 से लागू करेंगे"।

- हालाँकि GST पर अपना वादा पूरा न कर पाने का दोष बिना किसी आधार के भाजपा के ऊपर लगा दिया। केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की बकाया राशि का मुद्दा लगातार भाजपा द्वारा उठाया गया और 2012 के अंत में वित्त मंत्री इस विषय पर समवेत स्वर की बात करते हैं। हम अप्रैल 2014 के काफी करीब हैं, अगर आवश्यकता हो तो अभी ही ऐसे मुद्दे हैं जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हल होना चाहिए।

निष्कर्ष

10 निष्कर्ष :

कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार वास्तव में इस देश के लिए भारी विपत्ति साबित हुई है। यह भारत के लोगों के केवल लिए दुख, दर्द, और निराशा की विरासत छोड़ कर जा रही है। इस सरकार के कुकर्मों जिनका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है, ने देश की नींव को हिलाकर रख दिया है। ये आरोप पत्र उसी निराशा के सार है. हम यह उम्मीद करते हैं कि इस सरकार और इसके पापों से मुक्त होने का समय आ गया है।

संलग्नक

किस प्रकार UPA ने भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया ?

अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया गया

यूपीए को एक मजबूत अर्थव्यवस्था निम्नलिखित व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ विरासत में प्राप्त हुई थी.

- उच्च विकास दर
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम राजकोषीय घाटा
- न्यूनतम महंगाई दर
- उच्च बचत दर
- विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में न्यूनतम विदेशी कर्ज

ध्वस्त विकास दर

Indictor	1997-98	2003-04	2012-13	2013-14
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर	4.3%	8.5%	4.96 %	4.6% (till Dec. 2013)

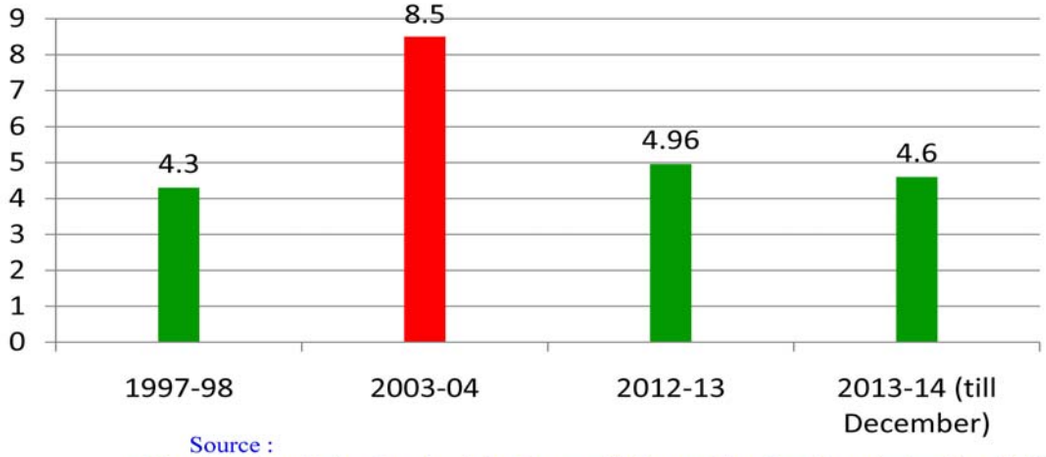

Source :
•Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013
•Economic Survey 2004-05
•CSO estimates of GDP for third quarter (Q3) of 2013-14

अनियंत्रित राजकोषीय घाटा

Indictor	1997-98	2003-04	2012-13
सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का % में	5.66 %	4.34 %	5.2 % (5.7 % in 2011-12)

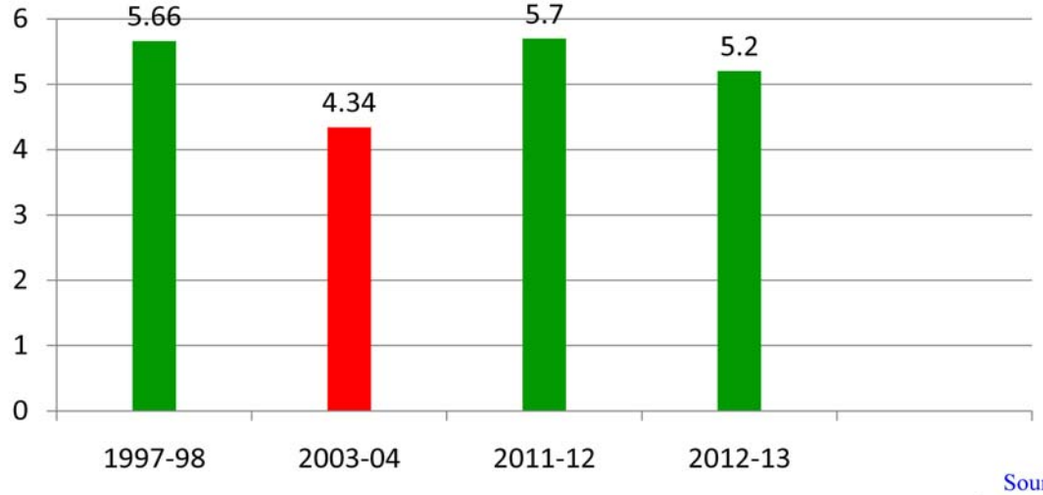

Source :
•Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013
• Budget Speech of Finance Minister for 2013-14 budget

चालू खाता घाटा – अधिशेष से घाटे तक

Indictor	1997-98	2003-04	2012-13
चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का%	-2 %	+2.7% (surplus)	-4.8% (deficit)

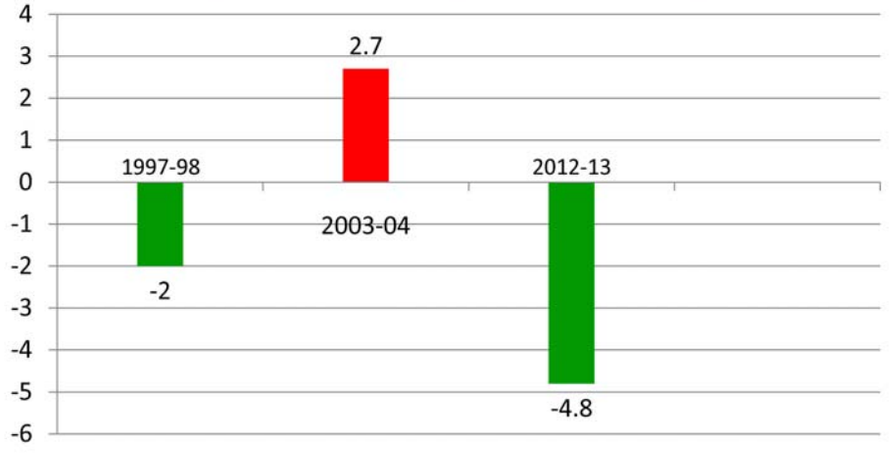

Source :
•Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013

रुपये की कीमत में भारी गिरावट

	1998-99	2003-04	29th August, 2013	March, 2014
Value of 1 $ in Rupees	42	45.9	67.7	61

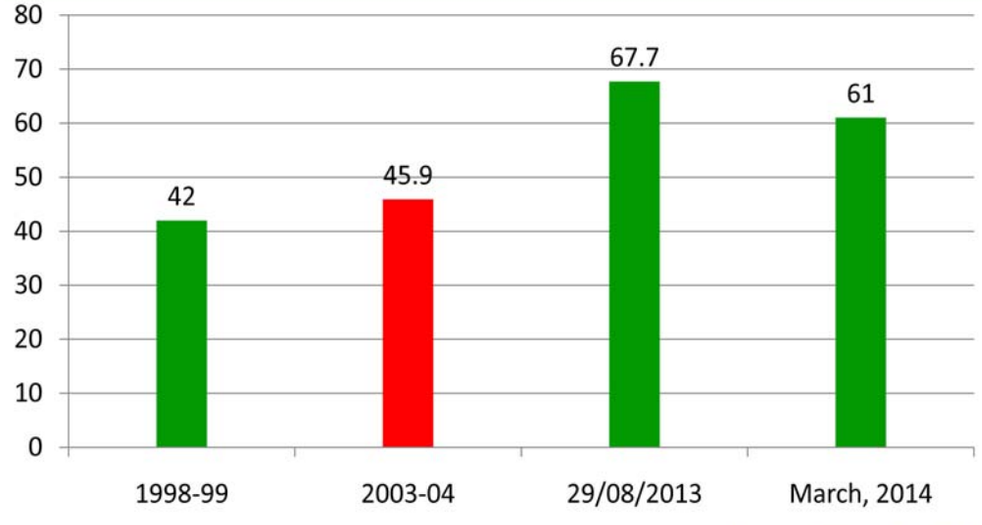

(Source : RBI Handbook of Statistics)

ध्वस्त औद्योगिक विकास

Indictor	1997-98	2003-04	2012-13	2013-14(Q3)
औद्योगिक विकास दर	4.01 %	7.32 %	2.1 %	-2 %

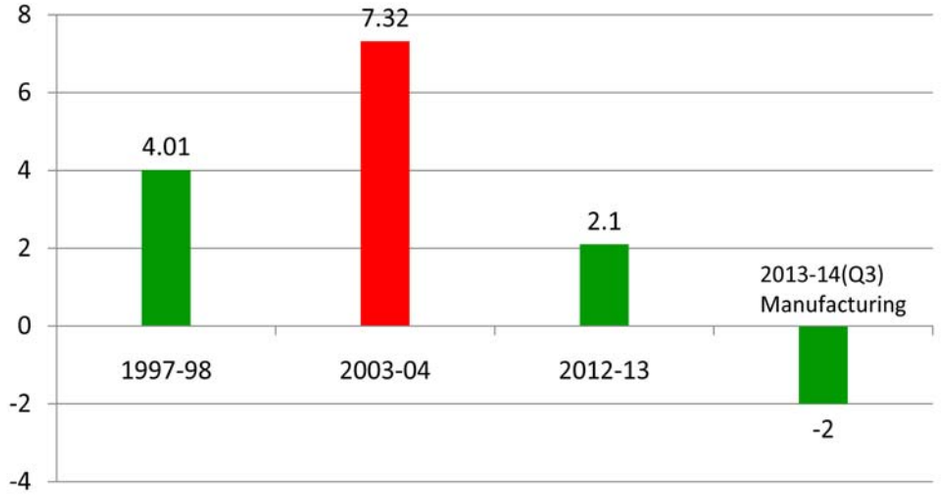

Source :
•Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013
•CSO estimates of GDP for third quarter (Q3) of 2013-14

अनियंत्रित महंगाई

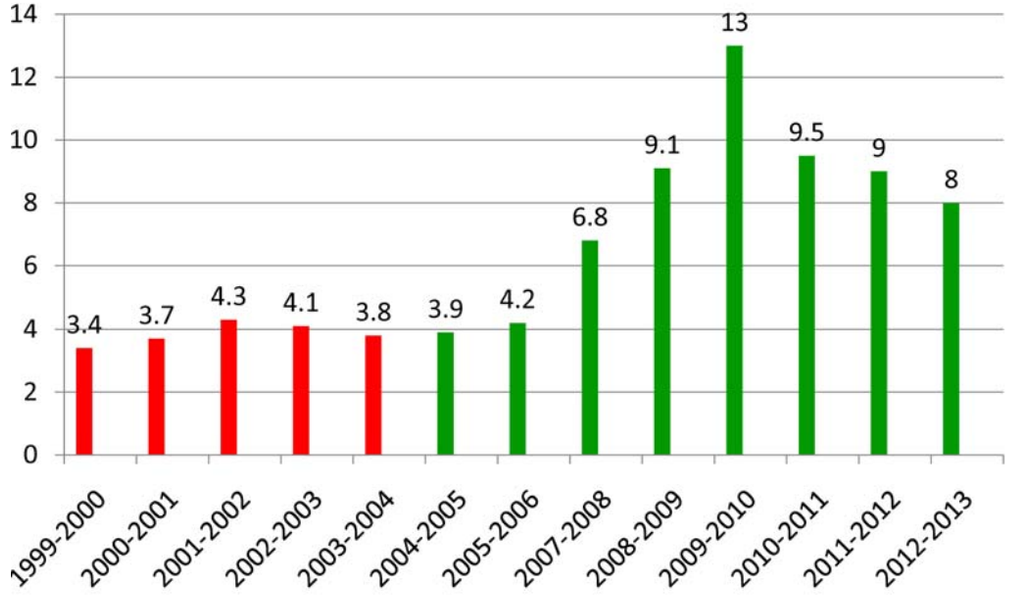

Source :
•Planning Commission Databook for Deputy Chairman, Planning Commission dated 18th Dec. 2013

रोजगार के अवसरों की समाप्ति

	1999-2000 to 2004-05	2004-05 to 2011-12
ोजगार अवसरों की सृजन संख्या (लाखों में)	60.7	15.44

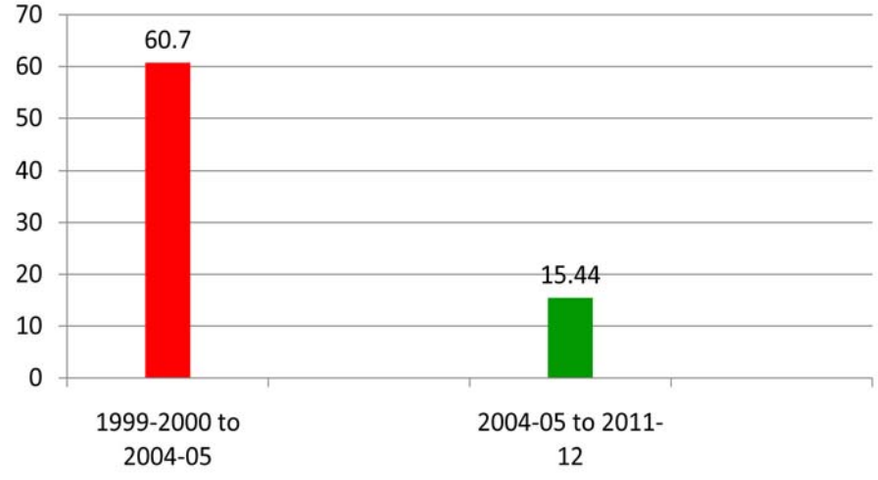

Source :
• NSSO 61st, 66th and 68th Round Survey

निर्माण क्षेत्र में रोजगारों का खत्म होना

	रोजगार में कुल वृद्धि (लाखों में)	
	1999-2000 to 2004-05	2004-05 to 2009-10
निर्माण क्षेत्र	11.72	-7.23

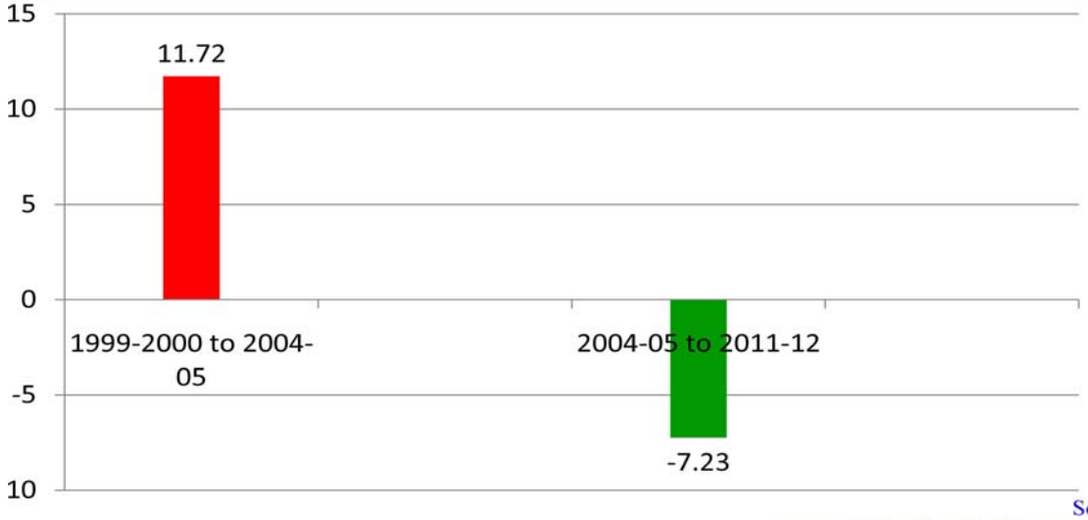

Source :
•NSSO 61st, 66th and 68th Round Survey

सेवा क्षेत्र में रोजगारों का खत्म होना

	रोजगार में कुल वृद्धि (लाखों में)	
	1999-2000 to 2004-05	2004-05 to 2009-10
सेवा क्षेत्र	18.77	-0.48

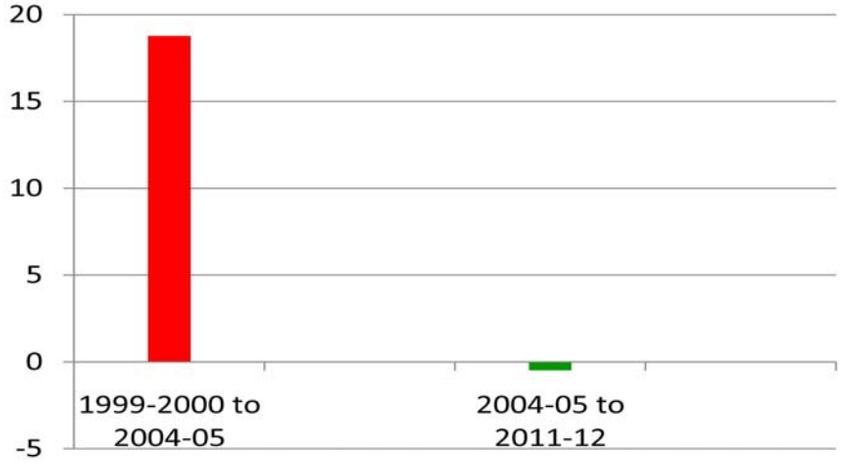

Source :
•NSSO 61st, 66th and 68th Round Survey

बुनियादी ढांचे की बर्बादी

बुनियादी ढांचे के मुख्य निम्नानुसार घटकों के बिना कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता.

- सड़कें
- बिजली
- इस्पात
- खनन
- बंदरगाह

हम देखेंगे कि किस प्रकार UPA सरकार के कुप्रबंधन ने विकास के इन सभी घटकों को पर कुठाराघात करके देश को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया.

सड़कें

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई (कि.मी.)	अतिरिक्त (कि.मी.)	अवधि (वर्ष में)	वार्षिक बढ़त (कि.मी)
1951	22193			
1997	34298	12105	46 years	**263**
2004	65569	31271	7 years	**4,467**
2012	76818	11249	8 years	**1,406**

46 वर्ष के शासन काल में कांग्रेस ने 12105 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जबकि 1997 से 2004 के अपने शासन काल के दौरान राजग ने 31271 किलोमीटर राजमार्गों क निर्माण किया. राजग सरकार ने प्रतिवर्ष 4467 Km की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया वहीं UPA के 2004 to 2012 शासन में प्रतिवर्ष 1406 Km राजमार्गों का निर्माण ही हो सका.

(Source : Basic Road Statistics from Ministry of Road Transport and Highways website http://www.morth.nic.in/showfile.asp?lid=839 and http://www.morth.nic.in/showfile.asp?lid=417)

बिजली

- UPA सरकार न तो स्थापित बिजली संयंत्रों का ठीक प्रकार से संचालन कर सकी न ही नए स्थापित बिजली संयंत्रों से बिजली पैदा कर सकी. सरकार ने इन संयत्रों को उन बैंको के लिए ऐसी अनर्जक संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया. जिन बैंको इनको वित्त पोषित किया था.

बिजली संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर

	1998-99	2004-05	2012-13
Plant load factor	64.6%	**74.8%**	69.9%

- नवंबर 2013 की केपीएमजी रिपोर्ट से एक निराशाजनक तस्वीर उभर कर आती है.
  - वर्ष 2011-12 के अंत में कोयला और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की कमी के कारण कारण बिजली संयंत्रों की 33000 मेगावार्ट के आसपास की क्षेमता अधर में लटक गई जिसकी वजह से इन बिजली संयत्रों में निवेश किये गए 1,00,000 करोड़ अलाभकारी साबित हो गए.
  - वर्ष 2011-12 के अंत तक 78 बिजली परियोजनाएं जिनसे 103000 MW बिजली का उत्पादन होना था, पर्यावरण से जुडी मंजूरी न मिलने कारण लंबित पड़ी हुई थी.

Source : 1. Central Electricity Authority's yearly reports at website www.cea.nic.in/reports/yearly_report.html)
2. KPMG Report "Recharging the Power sector" released in Nov. 2013

UPA न खनन क्षेत्र का ध्वस्त कर दिया.

कोयला

- भारत का कोयला भंडार 286 अरब टन है, जो कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है.
- 2012-13 में भारत का कोयला उत्पादन 557000000 टन था और इस अवधि में भारत ने 140 लाख टन कोयला आयत किया. आयातित कोयला महंगा होता है और यह बिजली उत्पादन को भी महंगा बनाता है.
- वर्ष 2003-04 मांग और आपूर्ति के मध्य मात्र 23.57 लाख टन का अंतर था

(Source : 1. Economic Survey 2012-13
•Coal Ministry's website : www.coal.nic.in/cpdoc.htm
•Source : Coal Ministry's Annual Report for 2004-05)

लोहा और इस्पात

- लोह अयस्क निर्यात : वर्ष 2012-13 में भारत ने 18.37 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया.
- हमारे पास इस्पात का सरप्लस उत्पादन हुआ करता था, लेकिन आज हमें स्टील के आयात और लौह अयस्क के निर्यात पर निर्भर हो गए हैं. यह औपनिवेशिक कालखंड के उन दिनों का स्मरण है जब हम कच्चा माल बेचकर तैयार उत्पाद आयत करते थे.

स्टील आयात/निर्यात (आंकड़े लाख टन में)

	2003-04	2011-12
आयत	1.75	6.83
निर्यात	5.21	4.04
अधिशेष / घाटा	+3.45	-2.79

Source : Annual Report of Steel Ministry for 2004-05 and 2012-13

बंदरगाह

2012-13 में भारत का विदेशी व्यापार 800 अरब डॉलर का था. जिसमें निर्यात 300 अरब डॉलर और आयात 500 अरब डॉलर का था. इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

- **भारतीय बंदरगाहों पर औसत वापसी समय (दिनों में)**

	1996-97	2004-05	2011-12
Turnaround time	7.8	3.41	5.05

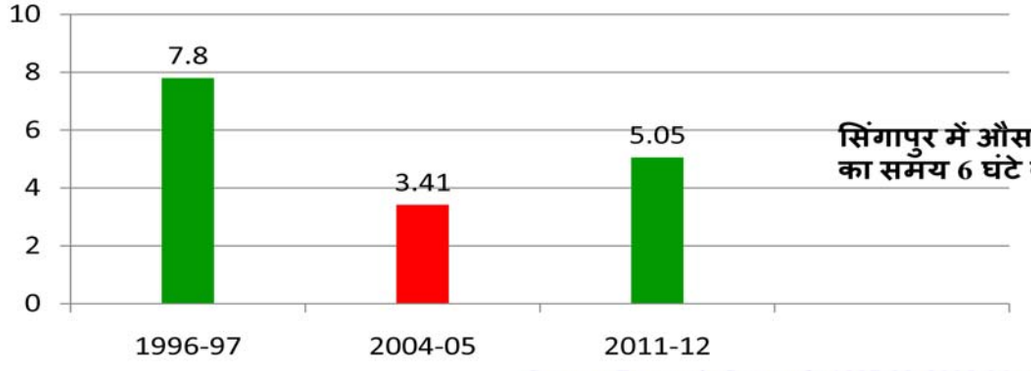

सिंगापुर में औसत वापसी का समय 6 घंटे का है.

Source : Economic Survey for1997-98, 2005-06 and 2012-13

Hkktik dUæh; puko lfefr d funs'k e dkxl d urRo okyh lçx ljdkj d nl o"kk d d'kklu ij vkjki i= cukus d fy, ,d mi lfefr cukbl xbA

---

lfefr d lnL;%

Jh xksihukFk eqM
miurk çfri{k ykd lHkk] Hkktik

Jherh vkjrh egjk
jk"Vh; lfpo] Hkktik

Jh dhjhV lkse;k
jk"Vh; dk;dkfj.kh lnL;] Hkktik

Jh jfo'kdj çlkn
miurk çfri{k jkT; lHkk] Hkktik

Jherh fueyk lhrkje.k
jk"Vh; çoDrk] Hkktik

Jherh ehuk{kh y[kh
jk"Vh; çoDrk] Hkktik

lk'ky ehfM;k] ekckby VDukykth vkfn ekè;ek ls turk d fopkj tkuu d fy, dkmM lkflx fuEukfdr

श्री माधव गर्ग

श्री नीरज शर्मा

श्री राजनील कामत

श्री विकास पाण्डे

श्री विनायक डालमिया

श्री नवरंग (भाजपा आई.टी. प्रकोष्ठ)